● वर्ष-5

● अंक-248

रायपुर, बुधवार
03 जून 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› दीपक बैज का बयान आदिवासी...

सीबीएसई में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

लोखंडे प्रशांत सीताराम नए चेयरमैन

सीनियर ब्यूरोक्रैट वरुण भारद्वाज को सचिव नियुक्त किया गया

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने सीबीएसई से जुड़े मामलों में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए बोर्ड के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है। इन अधिकारियों के स्थान पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम सीबीएसई के नए प्रमुख नियुक्त किया गया है। वहीं, सीनियर ब्यूरोक्रैट वरुण भारद्वाज सीबीएसई के नए सचिव होंगे।

गृह मंत्रालय के गृह विभाग के तहत अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवा दे रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम अब सीबीएसई की कमान संभालेंगे। वहीं, राहुल सिंह को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

19 अप्रैल 2027 तक होगा नए सचिव का कार्यकाल

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। शिक्षा मंत्रालय

के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक वरुण भारद्वाज को सीबीएसई के सचिव (निदेशक स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है।

यह नियुक्ति केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत प्रतिनियुक्ति के आधार पर, हिमांशु गुप्ता के स्थान पर लैटरल शिफ्ट के रूप में की गई है, जिसकी अवधि 19.09.2027 तक (यानी, केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत कुल 05 वर्ष का कार्यकाल) होगी।

इसके साथ ही सीबीएसई द्वारा ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ह्स्रू) सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति का गठन किया गया है।

एस. राधा चौहान होंगी कमेटी की अध्यक्ष

सूत्रों के अनुसार यह जांच समिति ओएसएम सेवाओं की खरीद, टेंडर प्रक्रिया और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करेगी। जारी आदेश के अनुसार इस जांच समिति की अध्यक्षता कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरपर्सन एस. राधा चौहान करेंगी। समिति को सीबीएसई द्वारा ओएसएम सिस्टम के लिए सेवाओं की खरीद से जुड़े सभी मामलों की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि समिति की अध्यक्ष एस. राधा चौहान आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों की सहायता भी ले सकेंगी। वहीं समिति को सचिवीय सहायता कैपेसिटी बिल्डिंग कमेटी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

एक महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट

सरकार ने जांच समिति को अपनी रिपोर्ट एक महीने के भीतर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपने के निर्देश दिए हैं।गौरतलब है कि पिछले दिनों से सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली, मूल्यांकन प्रक्रिया और ओएसएम टेंडर प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठे थे। इसी बीच छात्रों और विभिन्न संगठनों ने भी पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की थी। अब सरकार के इस फैसले को सीबीएसई मामलों में जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

पांच नए जजों को सीजेआई सूर्यकांत ने दिलाई शपथ

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के पांच नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई है। केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। सीजेआई ने जिन जजों को शपथ दिलाई है उनमें जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक भवन परिसर की तीसरी मंजिल स्थित ऑडिटोरियम में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ।

कानून मंत्री ने दी जानकारी

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को इस संबंध में सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद नए जजों की नियुक्ति की है। जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पांचों नए जजों को सीजेआई सूर्यकांत ने मंगलवार को शपथ ग्रहण कराया।

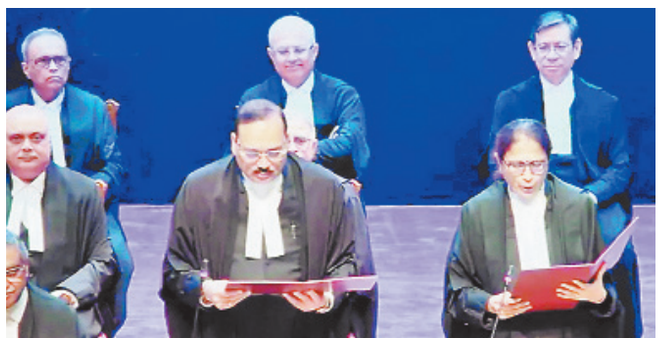

हाई कोर्ट के चार मुख्य न्यायाधीश भी शामिल

नए नियुक्त लोगों में हाई कोर्ट के चार मौजूदा मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। जस्टिस शील नागू पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (मूल हाईकोर्ट मध्य प्रदेश) के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, जस्टिस श्री चंद्रशेखर बॉम्बे हाई कोर्ट (मूल हाईकोर्ट झारखंड) के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, जस्टिस संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (मूल हाईकोर्ट दिल्ली) के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, और जस्टिस अरुण पल्ली जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट (मूल हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा) के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 22 मई और 27 मई को हुई अपनी बैठकों में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना की पदोन्नति की सिफारिश की थी।

रायपुर। प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को अपना जन्मदिन अपने निर्वाचन क्षेत्र रायगढ़ में जनता के बीच रहकर सादगी, सेवा और जनसंपर्क के साथ मनाया। सुबह से देर शाम तक जिलेभर से आए नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों, युवाओं और शुभचिंतकों ने उनसे मुलाकात कर जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-2 का सफल परीक्षण

नई दिल्ली›।भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रुद्रम-2 एयर-टू-सर्फेस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार मिसाइल ने तय लक्ष्य को बेहद सटीक तरीके से निशाना बनाया। इस सफलता को भारत की रक्षा ताकत और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण बेहद कठिन परिस्थितियों में किया गया। मिसाइल को हवा में छोड़े जाने के बाद उसने अपने सभी महत्वपूर्ण सिस्टम की

क्षमता साबित की और तय लक्ष्य को सटीकता से भेदा। चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के उपकरणों से मिले डाटा में सभी परीक्षण उद्देश्यों के सफल होने की पुष्टि हुई। इस परीक्षण के बाद रुद्रम-2 को भारतीय रक्षा प्रणाली के लिए अहम हथियार माना जा रहा है।रुद्रम-2 मिसाइल को पूरी तरह भारत में विकसित किया गया है। इसे हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने तैयार किया है। इस परियोजना में डीआरडीओ की कई अन्य प्रयोगशालाओं ने भी सहयोग किया। इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज शामिल हैं। इस परियोजना में सरकारी और निजी उद्योगों की भी बड़ी भूमिका रही। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, रीजनल सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थिनेस और मिसाइल सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी समेत कई संस्थाओं ने इस मिसाइल को तैयार करने और परीक्षण में मदद की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह सफलता भारत के रक्षा उद्योग और वैज्ञानिक क्षमता की बड़ी मिसाल है।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों और सभी सहयोगी संस्थाओं को इस सफलता के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह परीक्षण दिखाता है कि भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक अब तेजी से मजबूत हो रही है। उन्होंने इसे उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया।कहा जा रहा है कि रुद्रम-2 जैसी आधुनिक मिसाइलें भारतीय वायुसेना की हमलावर क्षमता को और मजबूत करेंगी। यह मिसाइल दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर दूर से सटीक हमला करने में सक्षम मानी जा रही है। इससे युद्ध के समय भारतीय सेना की रणनीतिक ताकत बढ़ेगी और विदेशी हथियारों पर निर्भरता भी कम होगी।

प्रमुख समाचार

कर्नाटक में कांग्रेस के सत्ता के खेल से प्रशासन ठप : शहजाद

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मंगलवार को कर्नाटक सरकार की आलोचना करते हुए उस पर शासन और प्रशासनिक कर्तव्यों की बजाय आंतरिक राजनीतिक संघर्षों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि काफी समय

से सत्ता में होने के बावजूद राज्य सरकार अभी भी सत्ता संघर्ष में लगी हुई है, जिसके कारण शासन व्यवस्था से जुड़े मुद्दों की अनदेखी हो रही है। पूनावाला ने कहा कि हमें लगा था कि कर्नाटक में तीन साल से चल रहे इस लगातार सत्ता संघर्ष के बाद अब आखिरकार प्रशासन और शासन व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, लेकिन वे अभी भी सत्ता संघर्ष में लगे हुए हैं। पूनावाला ने आगे आरोप लगाया कि नागरिक बुनियादी ढांचे, गड्ढों की मरम्मत, जलभराव, आर्थिक ऋण और भ्रष्टाचार जैसे प्रमुख मुद्दों पर राज्य नेतृत्व ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके बजाय, इस बात पर बैठकें हो रही हैं कि किसे कौन सा मंत्रिमंडलीय पद मिलेगा।

किरेन रिजिजू का राष्ट्र विरोधी ताकतों पर तीखा हमला

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को किसी का नाम लिए बिना, राष्ट्रविरोधी तत्वों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों पर तीखा हमला बोला और कहा कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग भारत की संप्रभुता और स्थिरता को कमजोर करने वाली ताकतों का बचाव करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। एक्स पर एक पोस्ट

में, रिजिजू ने कहा कि उन्हें भारत पर गर्व है, लेकिन उन लोगों की वे कड़ी आलोचना करते हैं जो कथित तौर पर राष्ट्रीय हितों से ऊपर अपने निजी हितों को प्राथमिकता देते हैं। रिजिजू ने लिखा कि मुझे भारत में रहने पर बहुत गर्व है, लेकिन मुझे उन स्वार्थी लोगों पर शर्म आती है जिनका कोई नैतिक मूल्य नहीं है, जो केवल धन के पीछे भागते हैं और आतंकवादियों, माओवादियों और भारत विरोधी गिरोहों और अपराधियों का बचाव करते हैं! लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व पर जोर देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत खुली बहस और असहमति के लिए प्रतिबद्ध है। बशर्ते कि ऐसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग राष्ट्र के हितों के खिलाफ काम करने वाले तत्वों का समर्थन करने के लिए न किया जाए।

शिवकुमार आज लेंगे कर्नाटक के नए सीएम पद की शपथ

बेंगलुरु । कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार 3 जून यानी बुधवार को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने की तैयार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवकुमार के साथ पहले चरण में करीब 10 से 12 विधायकों के मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बेंगलुरु के लोक भवन स्थित ग्लास हाउस में इस

भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां युद्धस्तर पर जारी हैं। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई उच्च राष्ट्रीय नेताओं के बेंगलुरु पहुंचने की उम्मीद है।इस प्रस्ताव पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला की देर रात हुई बैठक में चर्चा की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिवकुमार ने पार्टी नेतृत्व को सूचित किया है कि वह अपनी सरकार में किसी भी डिप्टी सीएम को नहीं चाहते हैं। इस मामले पर अंतिम फैसला राहुल गांधी द्वारा लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया ने डिप्टी सीएम पदों के लिए तीन नेताओं के नामों की सिफारिश की है।

टीएमसी के दागी नेताओं के लिए भाजपा के दरवाजे बंद

कोलकाता। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने मंगलवार को कहा कि पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं को शामिल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपना आधार जमीनी स्तर से बनाया है और वह दागी व्यक्तियों को शामिल नहीं करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा का तृणमूलकरण कभी नहीं होगा।

मीडिया से बात करते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। हमने बिना किसी बाहरी नेता को लाए 207 सीटें हासिल कीं। जनता ने टीएमसी के नेताओं के खिलाफ वोट दिया। इस बार हमारी राजनीतिक रणनीति निचले स्तर से शुरू हुई है। दागी लोगों को हम अपनी पार्टी में कैसे शामिल कर सकते हैं? भट्टाचार्य ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोलकाता में होने वाले विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुए टीएमसी को खुद के खिलाफ बताया और कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने पार्टी को नकार दिया है, जिसके चलते उनके लिए खेल खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को विरोध प्रदर्शन नहीं करने देगी।

इस्राइल-लेबनान संघर्ष पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

नई दिल्ली। कांग्रेस ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि वह लेबनान पर इस्राइल की सैन्य कार्रवाई और अमेरिका-ईरान समझौते को प्रभावित करने वाले घटनाक्रम पर पूरी तरह खामोश हैं। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि

अमेरिका और ईरान के बीच जारी वार्ता क्षेत्र में युद्ध को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर यह समझौता सफल होता है तो होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुल सकता है और वैश्विक तेल कीमतों पर दबाव कम होगा, जिसका भारत को सीधा लाभ मिलेगा। जयराम रमेश ने दावा किया कि इस्राइल की लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई इस समझौते के रास्ते में बड़ी बाधा बन रही है। उन्होंने कहा कि कई देशों ने लेबनान में इस्राइल के अभियान की आलोचना की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन हैं। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या उनकी तथाकथित पितृभूमि उनके वास्तविक मातृभूमि से अधिक महत्वपूर्ण है।

भाग 1

देश की सबसे बड़ी समस्या डेमोग्राफी परिवर्तन के खिलाफ केन्द्र की मुहिम

अभिनय आकाश

भारत में कितने घुसपैठिए रह रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका से कितने घुसपैठिए भारत में घुस चुके हैं। सरकार ने हाई लेवल कमिटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्या में परिवर्तन पे उच्च स्तरीय समिति बनाने का ऐलान कर दिया है और जो नोटिफिकेशन आया है उसमें घुसपैठ यानी इनफिल्ट्रेशन को बार-बार दोहराया गया है। देश की सबसे बड़ी समस्याओं में एक समस्या तमाम राज्यों में चेंज हो रही डेमोग्राफी। वो बात चाहे असम की हो, पश्चिम बंगाल की हो, बात हो बिहार की, उत्तराखंड की, झारखंड की या फिर तमाम और राज्यों की। डेमोग्राफी परिवर्तन बहुत ज्यादा हुआ। ऐसे में बंगाल जीतने के बाद अब एक नई सिरे से प्लानिंग हो रही है। यह प्लानिंग कौन कर रहा है? देश के गृह मंत्री अमित शाह। अगले कुछ दिनों में वो कुछ बहुत बड़े कदम उठाने वाले हैं। एक हफ्ते के अंदर गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर वाले जिलों में तीन चार बार गए हैं। एक बार त्रिपुरा गए। फिर वो बीकानेर, जैसलमेर में थे। यानी वेस्ट बाउंड्री से ले ईस्टर्न बाउंड्री तक लगातार यात्राएं कर रहे हैं। अमित शाह ने खुद को किसी प्रोजेक्ट में इतना इनवॉल्व किया है तो लोगों को सीरियस हो जाना चाहिए।

पिछले साल लाल किले से हाई पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन की घोषणा की थी और बाद में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर को 2025 से 11 सितंबर को इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी भी दे दी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इस कमेटी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि घुसपैठ और इन अन्य कारणों से अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने कमेटी का गठन कर लिया है। अमित शाह की पोस्ट का पहला शब्द था घुसपैठ। डेमोग्राफिक बदलाव के पूरे नैरेटिव के पीछे घुसपैठ शब्द बड़ा अहम है। पीआईबी ने प्रेस इनफेशन ब्यूरो ने कमेट को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया है।

पीआईबी के नोटिफिकेशन में लिखा है कि डेमोग्राफिक चेंज हमारी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक संरचना से जुड़ी गंभीर समस्या है। यह कमेटी अवैध प्रवास यानी घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस का व्यापक एनालिसिस करेगी और फिर इसका समाधान भी बताएगी।

क्या-क्या स्टडी करना है और रिपोर्ट में क्या बताएगी उसको आठ पॉइंट्स में बताया गया है। अलग-अलग इलाकों में डेमोग्राफिक चेंज और अवैध घुसपैठ से पैदा हुई समस्याओं की स्टडी डेमोग्राफिक चेंज के पीछे के कारण क्या है? क्या बॉर्डर पार की घुसपैठ है? रोजगार के मौके या दूसरे सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े कारण हैं? क्यों कुछ इलाकों में असामान्य तरीके से लोगों की बसावट बढ़ी है? या फिर प्लान करने में यह सब हो गया है। अलग-अलग धर्मों और सामाजिक समुदायों की आबादी में हो रहे बदलावों की स्टडी का फोकस भी उन पॉइंट्स पर है जहां देश की आबादी बढ़ने के सामान्य पैटर्न से अलग पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब अवैध प्रवासियों की पहचान हिरासत और उन्हें डिपोर्ट करने यानी वापस भेजने के लिए आसान निष्पक्ष और तय समय वाली व्यवस्था बनाने के सुझाव भी मांगे गए हैं। और सीमा सुरक्षा जनसंख्या नियंत्रण और आइडेंटिफिकेशन को मजबूत करने के लिए नई व्यवस्था कैसे बने इस पर भी काम होगा। अवैध घुसपैठ और उससे पैदा हुए जनसंख्या असंतुलन से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल के लिए सुझाव की बात भी कही गई है। जरूरत पड़ने पे जनसंख्या बदलाव और घुसपैठ से निपटने के लिए अन्य जरूरी सुझाव भी इसमें निहित है। ये सारे बिंदु पीआईबी के नोटिफिकेशन में लिखे हुए हैं।

गृह मंत्रालय के टेबल पर आईबी की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि जेएनजी आंदोलन के बहाने युवाओं को भड़काने की कोशिश में लगे लोग कौन हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ सालों के पिछले 10-20 पत्थरबाजी की घटनाओं के पैटर्न को देखे तो ज्यादातर घुसपैठिए थे। पत्थरबाजी, आगजनी और सड़कों पर तोड़पोड़ की घटनाओं में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की संलिप्त वाला भी इंसिडेंट जोड़ा गया है। आईबी की रिपोर्ट बताती है कि चाहे वो दिल्ली दंगे हो या नोएडा में हिंसा हो या कहीं भी अगर पत्थरबाजी होती है तो पत्थर फेंकने वालों की जब पहचान की गई तो इसमें बड़े पैमाने पर रोहिंग्या बांग्लादेशी पकड़े गए। ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है।

-क्रमशः

बीजापुर के कोंडापल्ली में सुशासन तिहार, सीएम साय ने लगाई चौपाल

सुशासन तिहार के तहत बीजापुर के दुर्गम कोंडापल्ली में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे. यहां पर उन्होंने चौपाल लगाई.

बीजापुर। बीते 40 साल से बीजापुर में नक्सलवाद ने जड़ें जमाी हुई थी। 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद का खात्मा हुआ। अब बीजापुर में विकास की बयार बह रही है। नक्सल क्षेत्र के रूप में पहचान रखने वाले कोंडापल्ली में अब विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। इसी के तहत मंगलवार 2 जून को कोंडापल्ली में सुशासन तिहार मनाया गया। सुशासन तिहार में सीएम विष्णुदेव साय कोंडापल्ली पहुंचे। यहां पर चौपाल लगाई और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत यहां चौपाल लगाकर सीधे ग्रामीणों से संवाद किया। इस अवसर पर क्षेत्र की दस से अधिक ग्राम पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे और अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा। चौपाल में पहुंचे ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पेयजल, सिंचाई और बैंकिंग सुविधाओं की कमी को लेकर सीएम साय के सामने मांगें रखी। कई ग्रामीणों ने बताया कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। कोंडापल्ली जैसे क्षेत्र, जो कभी नक्सल गतिविधियों के लिए जाने जाते थे, अब धीरे-धीरे विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।

सरकार का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में शांति, विकास और विश्वास का वातावरण स्थापित करना है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

सीएम ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की भी बात कही और बताया कि क्षेत्र में दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए करीब 2 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और खेती की स्थिति में सुधार आएगा।

सुशासन तिहार के अवसर पर ग्रामीणों की कई समस्याओं का समाधान हुआ।सुशासन तिहार से कोंडापल्ली में विकास की नई उम्मीद जगी है। प्रशासन और सरकार के गांव में पहुंचने से ग्रामीणों को यह भरोसा मिला है कि उनकी समस्या अब सीधे सरकार तक पहुंच रही है।

बकावंड तहसील के पटवारी पर गंभीर आरोप

कागजात बनाने के नाम पर कई लोगों से पैसे ठगने की शिकायत

जगदलपुर। ग्राम पंचायत मैलबेड़ा के लोगों ने बकावंड तहसील के भीतर आने वाले कोलावल हल्का के पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पटवारी ने कथित तौर पर लोगों से जमीन के कागजात बनाने के लिए गलत तरीके से पैसे लिए। गांव के कई लोगों ने बताया कि उनके पटवारी ने पैसे लिए लेकिन काम नहीं किया। गांव के लोग बताते हैं कि अब वो पटवारी कहीं और तबादला होकर चला गया है। इसकी वजह से वो अपने पैसे मांगने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।पटवारी पर आरोप है कि पट्टा, नामांतरण, सीमांकन, सरकारी दस्तावेज और बाकी राजस्व संबंधी कार्यों को पूरा करने का भरोसा देकर उसने लाखों रुपए गरीबों से ले लिए। एक ग्रामीण ने तो यहां तक बताया कि उसने पटवारी को पैसे देने के लिए अपने बैल तक बेच दिए। पीड़ित बुजुर्ग किसान ने बताया कि उसके बाद भी उसका काम पटवारी ने नहीं किया।

एक किसान ने बताया कि जब वो अपने पैसे मांगने को लिए पटवारी को फोन करने लगा तो आरोपी पटवारी ने उसका फोन नंबर ही ब्लॉक कर दिया।ग्रामीणों का कहना है कि सालों से लंबित भूमि संबंधी मामलों को जल्द निपटाने का आश्वासन देकर पटवारी ने लोगों से अलग-अलग तरीके से रकम की वसूली की। पटवारी के खिलाफ अब पीड़ित गांव वाले लामबंद होकर एसडीएम से शिकायत कर रहे हैं। रताखण्डी निवासी मंगतू सहित पूरे गांव वाले यह चाहते हैं कि जितने भी ग्रामीण पटवारी से प्रभावित हुए हैं, उन्हें उनका पैसा वापस मिले और उच्च अधिकारी पटवारी पर कार्रवाई करें। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो कलेक्टर कार्यालय के घेराव को मजबूर होंगे।

कलेक्ट्रेट में जनदर्शन आत्मदाह की कोशिश

बीजेपी पार्षद पर लगाए गंभीर आरोप, मौके पर मचा हड़कंप

धमतरी। कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब जनदर्शन कार्यक्रम में पत्नी और दो बच्चो के साथ अपनी शिकायत लेकर पहुंचे एक शख्स ने मिट्टी तेल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। युवक को तत्काल रोककर सुरक्षित किया गया। जानकारी के अनुसार, युवक की पहचान रोहित सोनी के रूप में हुई है, जो धमतरी शहर के पोस्ट ऑफिस वार्ड स्थित साई बाबा मंदिर के पास का निवासी है। रोहित ने कलेक्टर को सौंपे गए आवेदन में परिवार सहित इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है।

उसका आरोप है कि वह और उसका परिवार पिछले करीब 60 वर्षों से बढ़ेश्वर महादेव मंदिर के समीप अपने मकान में निवास कर रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में मंदिर से जुड़े कुछ लोगों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उसे लगातार परेशान किया जा रहा है। रोहित सोनी ने आवेदन में आरोप लगाया है कि जब वह अपने मकान का निर्माण कार्य करा रहा था, तब 10 से 20 लोगों का समूह उसके निर्माणाधीन घर में घुस आया और काम बंद करा दिया। आरोप है कि उसे घर छोड़कर कहीं और चले जाने के लिए दबाव बनाया गया। युवक का कहना है कि उसे धमकी दी गई कि यदि उसने मकान नहीं छोड़ा तो उसके लिए स्थिति ठीक नहीं होगी। आवेदन में रोहित ने भाजपा पार्षद निलेश लुनिया और उनके कुछ साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि पार्षद और उनके समर्थक लगातार उस पर घर खाली करने का दबाव बना रहे हैं। युवक का आरोप है कि उसे कहा गया कि भाजपा की सरकार है और मैं भाजपा का नेता हूं, जहां जाना है जाओ, मैं देखता हूं तुम यहां कैसे रहते हो। पीड़ित का यह भी आरोप है कि उसके घर आने-जाने के रास्ते को खोदकर गड्ढा बना दिया गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। उसने दावा किया कि कई बार नगर निगम और संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत करने के बावजूद उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। न्याय नहीं मिलने से परेशान होकर वह जनदर्शन कार्यक्रम में अपने दो बच्चो और पत्नी के साथ अपनी बात रखने पहुंचा था।

जनदर्शन के दौरान अचानक उसने अपने ऊपर मिट्टी तेल छिड़क लिया और आत्मदाह का प्रयास करने लगा। हालांकि वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए उसे रोक लिया। घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

आईटीआई जनकपुर में करें ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून तक

एमसीबी। जिले के युवाओं के लिए रोजगारपरक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर उपलब्ध हुआ है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) जनकपुर में सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 29 मई 2026 से 15 जून 2026 तक प्रवेश के लिए निर्धारित वेबसाइट बहपजप.कडउपेपवदे.दपब.पद पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जनकपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्थान में कोपा (एससीवीटी) एक वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 48 सीटें, विद्युतकार (एससीवीटी) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 20 सीटें तथा सिलाई टेक्नोलॉजी एक वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 40 सीटें उपलब्ध हैं। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर बेहतर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न की जाएगी। प्रथम चरण में 16 जून से 22 जून तक प्रथम चयन सूची जारी की जाएगी तथा 23 जून से 25 जून तक चयनित अभ्यर्थियों का प्रवेश होगा। द्वितीय चरण में 26 जून से 3 जुलाई तक द्वितीय चयन सूची जारी की जाएगी तथा 4 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होगी।

अफीम के साथ युवक गिरफ्तार

जगदलपुर। बस्तर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 133.3 ग्राम अवैध अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जगदलपुर के गोयलबाड़ी तिराहा के पास अफीम बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी जगदीश चौधरी को पकड़ा। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बरामद पदार्थ को शिलाजीत बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने स्न्रस्रुकिट से जांच कराई, जिसमें पदार्थ अफीम पाया गया। आरोपी मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला है और जगदलपुर में किराए के मकान में रहकर नशे का कारोबार कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 66 हजार 500 रुपये कीमत की 133.3 ग्राम अफीम जब्त की है। आरोपी के खिलाफ ह्लष्ठक्क्र एक्ट की धारा 18(क्च) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बस्तर पुलिस ने साफ कहा है कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

19 प्रशिक्षु उपनिरीक्षक और 2 सूबेदार 10 महीने के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए जांजगीर-चांपा में पदस्थ

जांजगीर-चांपा। राज्य पुलिस अकादमी रायपुर से बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद 19 प्रशिक्षु उपनिरीक्षक और 2 प्रशिक्षु सूबेदारों को 10 महीने के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए जांजगीर-चांपा जिले में पदस्थ किया गया है। प्रशिक्षु अधिकारियों की तैनाती से जिला पुलिस बल को नई ऊर्जा और अतिरिक्त कार्यक्षमता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय ने सभी प्रशिक्षु अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें जिला पुलिस की कार्यप्रणाली, कानून-व्यवस्था संधारण और पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। बैठक के दौरान एसपी ने कहा, पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी आम नागरिकों को न्याय दिलाना और उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करना है। उन्होंने प्रशिक्षुओं को अपराध विवेचना, मर्ग जांच, शिकायत एवं आवेदन जांच की प्रक्रिया को गंभीरता और निष्पक्षता के साथ संपादित करने के निर्देश दिए। साथ ही फरियादियों और आवेदकों के साथ सम्मानजनक, सौहार्दपूर्ण और मानवीय व्यवहार बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। प्रशिक्षु अधिकारियों को जिले के विभिन्न थाना और चौकियों में पदस्थ किया गया है, जहां उन्हें अपराध विवेचना, मर्ग जांच, शिकायत जांच और कानून-व्यवस्था ड्यूटी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा प्रधान आरक्षक मोहर्रिर कार्य, प्रधान आरक्षक गस्ती, रात्रि गश्त, पेट्रोलिंग, सीसीटीएनएस संचालन, संत्री ड्यूटी, मददगार कार्य, मुलजिम पेशी, न्यायालयीन कार्यवाही और बीट आरक्षक की जिम्मेदारियों की भी व्यावहारिक जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों और अनुभवी पुलिसकर्मियों द्वारा दी जाएगी। जिला व्यवहारिक प्रशिक्षण के तहत तीन प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों को सिटी कोतवाली में पदस्थ किया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

रामानुजगंज में सुशासन तिहार पर सुलझाई लोगों की समस्या

रामानुजगंज। रामानुजगंज में सुशासन तिहार के तहत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। जहां कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम की मौजूदगी में नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत करोड़ों रूपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास भूमिपूजन किया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ और सामग्री बांटी गई। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। रामानुजगंज नगरपालिका अंतर्गत आने वाले पंद्रह वार्ड के लिए काका लरंगसाय सुशासन तिहार के तहत समस्याओं का निवारण किया गया।आमजन की समस्या निराकरण के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम सहित कलेक्टर जिला पंचायत सीईओ सहित जिला प्रशासन के अफसर शिविर में पहुंचे। आम नागरिकों की उपस्थिति में लगभग 14 करोड़ 91 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया।

खैरागढ़ बाईपास रोड का निर्माण बरसों से अधूरा

खैरागढ़। खैरागढ़ कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। जिला बनने के बाद लोगों को यहां की समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी थी। उसके बावजूद आज भी यह बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। करीब 12 वर्ष पहले शुरू हुआ बाईपास निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो सका है। नतीजा यह है कि बड़े और भारी वाहन अब भी शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरने को मजबूर हैं, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा रही है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। खैरागढ़ को जिला बने तीन वर्ष बीत चुके हैं। जिला मुख्यालय बनने के बाद कलेक्ट्रेट, एसपी कार्यालय समेत कई प्रमुख सरकारी कार्यालयों में लोगों की आवाजाही बढ़ी है। इसके बावजूद शहर को भारी वाहनों के दबाव से राहत दिलाने वाला बाईपास अब तक अधूरा पड़ा है। हालात यह है कि डोंगरगढ़ से कवर्धा, बिलासपुर और अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहन तथा राजनांदगांव से खैरागढ़ जाने वाले वाहन शहर के बीचों बीच से गुजरते हैं। इससे मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति बनती है।

सामान नहीं मिला तो 25 लीटर पेट्रोल चुराकर भागा चोर

जगदलपुर। आपने कैश, ज्वेलरी या किसी कीमती सामान की चोरी की घटना जरूर सुनी होगी, लेकिन महंगाई के दौर में अब चोर पेट्रोल पर हाथ साफ करने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां अज्ञात चोर ने नकदी या कीमती सामान की बजाय 25 लीटर पेट्रोल से भरा जर्किन, सिगरेट और ड्राई फ्रूट पर हाथ साफ कर दिया। घटना पुलिस थाना से 50 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, घटना भानपुरी में सोमवार और मंगलवार के दरमियानी रात करीब 1ः52 बजे की है। आरोपी तीन ठेला नुमा दुकानों के पास पहुंचा। उसने दुकानों के ताले तोड़े और करीब 20 मिनट तक वहां मौजूद सामान खंगालता रहा। इसके बाद करीब रात 2ः12 बजे आरोपी अपने सिर पर 25 लीटर पेट्रोल से भरा जर्किन, सिगरेट और ड्राई फ्रूट्स लेकर मौके से फरार हो गया। पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई।

सुकमा में दूरस्थ गांवों तक पहुंची हेल्थ सर्विस

सुकमा। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से कभी नक्सल प्रभावित रहा सुकमा जिले के सुदूर गांव गोगुण्डा में अब उम्मीद का नया सवेरा हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से जिला चिकित्सालय सुकमा ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गोगुण्डा के 10 मोतियाबिंद मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया। इस सफल सर्जरी के जरिए इन ग्रामीणों के जीवन के अंधेरे को दूर कर उन्हें नई दृष्टि का अनमोल उपहार दिया गया है। यह पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग की संवेदनशीलता और सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली का बेहतरीन उदाहरण है।स्वास्थ्य विभाग की टीमें खुद दुर्गम गांवों में पहुंचकर घर-घर सर्वे कर रही हैं और मोतियाबिंद के मरीजों की पहचान कर रही हैं। इसके बाद, मरीजों को पूरे सम्मान के साथ विशेष वाहनों से जिला चिकित्सालय लाया जाता है। जहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में उनका निःशुल्क इलाज होता है।

कार के दरवाजे में गुप्त चेंबर बनाकर छिपाया था गांजा

दुर्ग। दुर्ग में भी पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में गांजा सप्लाई करने वाले और खपाने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 7 लाख 25 हजार रुपए का 14 .5 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपियों ने गांजे को कार के दरवाजे में गुप्त चेंबर बनाकर छिपाया था, लेकिन गांजे की खुशबू ने पूरा राज खोल दिया। कुम्हारी थाना पुलिस और एसीसीयू दुर्ग की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी ओडिशा से एक क्रेटा कार में अवैध गांजा परिवहन कर महासमुंद, रायपुर होते हुए दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में खपाने के लिए ला रहे हैं, जिसके बाद टीम ने कुम्हारी ओवरब्रिज के नीचे घेराबंदी कर रायपुर की ओर से आ रही संदिग्ध क्रेटा कार को रोक लिया। टीम ने जब कार की जांच की, तो उसके अंदर से गांजे की तेज गंध आ रही थी। गंध आते ही पुलिस का शक यकीन में बदल गया। गाड़ी की बारीकी से तलाशी लेते हुए दरवाजों के फाइबर को हटाया गया, तो अंदर छिपे गांजे के पैकेट देखकर पुलिस भी हैरान रह गई।

68 गांव के ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, अंतागढ़ में किया चक्काजाम

भानुप्रतापपुर। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा में पिछले 6 दिनों से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 पंचायत के 68 गांव के लोग धरना दे रहे हैं। आज आंदोलन का 7वां दिन है। मांगें पूरी नहीं होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने अंतागढ़ में चक्काजाम कर दिया है। इसके चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। भानुप्रतापपुर से नारायणपुर मार्ग पर वाहनों का आवागमन थम गया है। वहीं आंदोलनरत ग्रामीणों में सांसद और विधायक के प्रति भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इधर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पाटेश्वर धाम से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर आदिवासी समाज के हजारों लोगों ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई, जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड्स को पार कर कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रवेश कर अपनी मांगों को लेकर वहीं धरने पर बैठ गए। समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही चूल्हे में खाना बनाकर प्रदर्शनकारियों को खिलाया। आदिवासी समाज के लोगों का आरोप है कि पाटेश्वर धाम के बालक दास के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि करीब 12 एकड़ से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि पाटेश्वर धाम में पंचायत के प्रस्ताव के बिना एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्माण कार्य कराया गया है। उन्होंने इन निर्माणों को अवैध बताते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। साथ ही जलकैनी माता स्थल को नुकसान पहुंचाने और उसे पाटने का भी आरोप लगाया गया। ग्राम सभा की अनुमति के बिना रूढिजन्य पारंपरिक सीमा क्षेत्र के भीतर जल, जंगल, जमीन पर कब्जा, अवैध खनन एवं निर्माण कार्य पर कार्रवाई व 17 मई से 15 जून 2026 तक प्रस्तावित मेला कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

ये हैं ग्रामीणों की मांगें

जिला सहकारी बैंक की स्थापना की जाए। ब्लॉक मुख्यालय वापस पखांजूर से कोयलीबेड़ा लाया जाए। कोयलीबेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय कोयलीबेड़ा में खोला जाए। डीएमएफ राशि प्रभावित क्षेत्र में शत-प्रतिशत खर्च किया जाए। जर्जर स्कूल आश्रम की मरम्मत की जाए। कॉलेज की मांग पूरी की जाए। खाद-बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। अंतागढ़ से कोयलीबेड़ा रोड का डामरीकरण किया जाए। राजस्व प्रकरणों के सरलीकरण के लिए कोयलीबेड़ा तहसील को अनुभाग अंतागढ़ में जोड़ा जाए।

दो वनरक्षक सस्पेंड, 6.77 करोड़ का नुकसान

बड़े अफसरों पर एक्शन कब?

बीजापुर। ईटपाल स्थित तेंदूपत्ता गोदाम में 25 मई 2026 को भीषण अग्निकांड हुआ। इस घटना में लगभग 6.77 करोड़ रुपये मूल्य का तेंदूपत्ता जलकर नष्ट हो गया। वन विभाग ने पहली कार्रवाई करते हुए दो वनरक्षकों को निलंबित किया है। जिला यूनियन बीजापुर की आठ प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 13 तेंदूपत्ता लॉट गोदाम में रखे थे। वनमंडलाधिकारी बीजापुर ने गोदाम सहायक सुनील बुरका को निलंबित कर दिया है। वनरक्षक कामेश्वर एनका के निलंबन का प्रस्ताव इंद्रावती टाइगर रिजर्व के उप निदेशक को भेजा गया है। वनक्षेत्रपाल और उपवनक्षेत्रपाल स्तर के गोदाम प्रभारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा भी उच्च कार्यालय को भेजी गई है। विभाग ने नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कंपनी से दावा प्रक्रिया शुरू की है। विभाग का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने घटना के आठ दिन बाद भी बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई न होने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि विभाग छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रहा है। बड़े नियंत्रणकर्ता अधिकारियों और गोदाम प्रभारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों के अनुसार, घटना के तीसरे दिन ही डीएफओ को हटा दिया गया था। लेकिन आठ दिन बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जांच टीम भी मौके पर नहीं पहुंची है।

संक्षिप्त समाचार

मंदिर हसौद थाना क्षेत्र स्थित मिवान स्टील प्लांट में लगी भीषण आग

रायपुर। राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र स्थित मिवान स्टील लिमिटेड प्लांट में मंगलवार तड़के भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी विकराल थी कि उसकी ऊंची लपटें और धुएं का घना गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आग मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे प्लांट परिसर में लगी। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाडियां मौके पर रवाना की गईं। दमकल कर्मियों ने पहुंचते ही आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया, लेकिन आग की तीव्रता अधिक होने के कारण इसे नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल नुकसान का आकलन नहीं लग पाया है लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है।

1 अगस्त से रायपुर- कोरबा - रायपुर हसदेव एक्सप्रेस का नियमित परिचालन

रायपुर। यात्रियों की मांग एवं सुविधा अनुसार रायपुर रेल मंडल ने गाड़ी संख्या 18249/ 18250 रायपुर -कोरबा -रायपुर जो सप्ताह में 4 दिन चलती है का 1 अगस्त से परिचालन नियमित रूप से शुरू किया जा रहा है। यह जानकारी रेलवे रायपुर मंडल के जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई। गाड़ी संख्या 18251/18252 रायपुर- कोरबा - रायपुर हसदेव एक्सप्रेस को जो सप्ताह में 3 दिन चलती है। 1 अगस्त से मर्ज कर कर गाड़ी संख्या 18249 /18250 रायपुर- कोरबा - रायपुर हसदेव एक्सप्रेस के रुप में प्रतिदिन चलाई जाएगी । विभिन्न श्रेणी के 15 एलएचबी कोच के साथ चलाई जाएगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सहायता राशि से आसान हुई खेती

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुरूप किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मुंगेली जिले के किसानों के लिए सहारा बन रही है। जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से हजारों किसान लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। योजना के माध्यम से मिलने वाली आर्थिक सहायता किसानों को खेती-किसानी में बड़ी राहत प्रदान कर रही है। लोरमी विकासखंड के ग्राम करूहानार निवासी किसान चुन्नूलाल साहू ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सराहना करते हुए कहा कि योजना के तहत प्रतिवर्ष मिलने वाली 06 हजार रुपये की सहायता राशि खेती-किसानी के कार्यों में काफी उपयोगी साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि इस राशि से बीज, खाद एवं कृषि कार्यों में जरूरी खर्च आसानी से पूरे हो जाते हैं, जिससे आर्थिक बोझ कम हुआ है। किसान श्री साहू ने बताया कि उन्हें अब तक योजना की 22 किश्तों का लाभ प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही यह योजना किसानों के लिए संबल बन गई है। समय पर मिलने वाली राशि से खेती की तैयारी में सुविधा होती है और कृषि कार्यों में आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की किसान हितैषी योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

रामाराम जलाशय योजना के जीर्णोद्धार हेतु 1.16 करोड़ स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा सुकमा जिले के विकासखण्ड सुकमा के अंतर्गत रामाराम जलाशय योजना के जीर्णोद्धार कार्य के लिए 1 करोड़ 16 लाख 6 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह पहल सुकमा क्षेत्र में कृषि विकास को गति देने और स्थानीय किसानों की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। इस योजना के प्रस्तावित कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर क्षेत्र के स्थानीय किसानों को 69 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलने लगेगी। जल संसाधन विभाग द्वारा इस योजना के कार्यों को समय पर और गुणवत्तापूर्वक संपन्न कराने के लिए मुख्य अभियंता, गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग (जगदलपुर) को आवश्यक दिशा-निर्देश और प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। योजना के पूर्ण होने के बाद, रूपांकित सिंचाई क्षमता में आ रही कमी पूरी होगी और पूरे क्षेत्र को पर्याप्त सिंचाई का लाभ मिलेगा।

बिलासपुर-यलहंका (बेंगलुरु)-बिलासपुर के मध्य 5-5 फेरों के लिए आज से चलेगी समर स्पेशल ट्रेन

रायपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बिलासपुर-यलहंका(बेंगलुरु)-बिलासपुर के मध्य यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये 5-5 फेरे के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। गाड़ी संख्या 08261 बिलासपुर- यलहंका(बेंगलुरु)-समर स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से प्रत्येक बुधवार को 3 जून से 1 जुलाई तक चलेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 08262 यलहंका (बेंगलुरु)-बिलासपुर समर स्पेशल ट्रेन यलहंका से प्रत्येक गुरुवार को 04 जून 2026 से 02 जुलाई 2026 तक चलेगी।इस गाड़ी में 2 एसएलआरडी,4 सामान्य, 10 स्लीपर, 4 एसी-।।। सहित कुल 20 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी ।

40 लाख की अत्याधुनिक चिकित्सा सामग्री से सशक्त होंगी स्वास्थ्य सेवाएं : मिश्रा

आईडीबीआई बैंक के सहयोग से जिला अस्पताल एवं भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज को मिला बड़ा संबल

रायपुर। जनसेवा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के प्रति अपनी सतत प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री पुरंदर मिश्रा के प्रयासों से जिला अस्पताल रायपुर एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज रायपुर को लगभग 40 लाख रुपए मूल्य की अत्याधुनिक चिकित्सा सामग्री प्राप्त हुई है। यह महत्वपूर्ण सहयोग आईडीबीआई बैंक द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत प्रदान किया गया है।

इस अवसर पर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा ने आईडीबीआई बैंक के महाप्रबंधक/वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रमुख श्री आशीष त्रिपाठी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज और संस्थाओं की सहभागिता से ही जनकल्याण के कार्यों को नई दिशा और गति मिलती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में किया गया यह सहयोग हजारों मरीजों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा तथा अस्पतालों में उपचार सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। बैंक द्वारा जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज को सेमी फाउलर बेड, सेमी फाउलर गद्दा, फाउलर बेड, फाउलर गद्दा, बेड साइड लॉकर, बेड ओवर टेबल तथा आईवी स्टैंड जैसी आवश्यक एवं आधुनिक चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इन संसाधनों के जुड़ने से मरीजों को बेहतर सुविधा, आरामदायक उपचार व्यवस्था तथा चिकित्सकीय सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना समाज के प्रत्येक वर्ग की जिम्मेदारी है। आईडीबीआई बैंक ने जिस संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया है, वह निश्चित रूप से अन्य संस्थाओं के लिए प्रेरणादायी उदाहरण है। यह सहयोग केवल चिकित्सा उपकरणों का वितरण नहीं, बल्कि मानवता और जनसेवा के प्रति एक सशक्त संकल्प का परिचायक है। उन्होंने कहा कि आज जब गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है, ऐसे समय में निजी संस्थानों और सामाजिक संगठनों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। आईडीबीआई बैंक द्वारा प्रदान की गई यह सामग्री अस्पतालों की आधारभूत व्यवस्थाओं को मजबूत करेगी तथा जरूरतमंद मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री मिश्रा ने विशेष रूप से आईडीबीआई बैंक के श्री आशीष त्रिपाठी महाप्रबंधक/वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रमुख आई.डी.बी.आई.बैंक की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सकारात्मक सोच और जनहितैषी पहल के कारण यह महत्वपूर्ण सहयोग संभव हो पाया है। समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता और सेवा भावना प्रशंसनीय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी आईडीबीआई बैंक इसी प्रकार जनकल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक विकास से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करता रहेगा। %स्वस्थ नागरिक ही समृद्ध समाज और विकसित राष्ट्र की आधारशिला हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में किया गया प्रत्येक प्रयास जनसेवा का श्रेष्ठतम स्वरूप है। आईडीबीआई बैंक द्वारा दिया गया यह सहयोग निस्संदेह हजारों लोगों के जीवन में आशा, विश्वास और बेहतर स्वास्थ्य का नया संबल बनेगा।

जनता की लिक्विडिटी छीनकर गोवा के होटलों में निवेश कर रही थी कांग्रेस : भाजपा

- **प्रदेश प्रवक्ता पाण्डेय ने शराब घोटाले को लेकर ईडी के पूरक आरोप पत्र में हुए चौंकाने वाले खुलासों के बाद कांग्रेस पर बोला तीखा हमला**

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पाण्डेय ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पेश किए गए छठवें पूरक आरोप पत्र का हवाला देते हुए कहा कि इसमें कांग्रेस सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार के नए और चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं।

पाण्डेय ने आरोप लगाया कि इस महाघोटाले के कारण आज छत्तीसगढ़ में नकदी और मुद्रा तरलता (लिक्विडिटी) का भारी अभाव दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता का हक मारकर यहाँ का पैसा दूसरे राज्यों में अवैध रूप से निवेश किया गया, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था काफी पीछे चली गई है। श्री पाण्डेय ने बताया कि शराब घोटाले की काली कमाई का लगभग 110 करोड़ रुपया कथित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र के माध्यम से नॉर्थ गोवा के होटल वेस्टिन को खरीदने में लगाया गया है। ईडी ने इसके पुख्ता प्रमाण चार्जशीट में जोड़े हैं। इस पूरे घोटाले में अब तक लगभग 89 आरोपियों को नामजद किया गया है, और अपराधियों से कुल 1,000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को ईडी द्वारा फ्रीज या सीज किया जा चुका है। ताजा चार्जशीट में ही 200 करोड़ रुपए की नई बेनामी और अवैध सम्पत्ति का पता चला है। श्री पाण्डेय ने मांग की है कि बेनामी ट्रांजेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इस भयावह खेल पर कांग्रेस पार्टी को जनता के सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ की यह लूट अकेले नहीं हुई। इसमें राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी और बड़े व्यवसायियों की तिकड़ी का एक मजबूत सिंडिकेट सक्रिय था। इस सिंडिकेट के कई तत्कालीन मंत्री और अधिकारी आज भी जेलों में बंद हैं। श्री पाण्डेय ने सवाल उठाया कि इतने बड़े घोटाले और गंभीर आरोपों के बाद भी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? कांग्रेस के पास केंद्रीय एजेंसियों पर दुरुपयोग का आरोप लगाने के अलावा कोई सीधा स्पष्टीकरण नहीं है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के गायब होने पर भी श्री पाण्डेय ने जवाब मांगा और दो टूक कहा कि इस पूरे सिंडिकेट को चलाने वाला और इसका असली बॉस वही है जो उस समय सत्ता का संचालन कर रहा था। पूरी जाँच से साफ है कि राजनेताओं के संरक्षण में ही यह लूट मची थी। कांग्रेस को इधर-उधर की बात करने के बजाय छत्तीसगढ़ की जनता को सीधे-सीधे जवाब देना चाहिए।

क्षेत्र का समग्र विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : चौधरी

वित्त मंत्री ने 32.15 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

रायपुर। प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी ने अपने जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर पुसौर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत मिडमिडा, त्रिभौना, तुरंगा, कोतासुरा एवं कोड़ातराई का दौरा कर करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास, भूमिपूजन एवं लोकार्पण करते हुए क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने का संकल्प दोहराया। इस दौरान कुल 32 करोड़ 15 लाख रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।

ग्रामीणों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि प्रदेश और रायगढ़ की जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है, उसे विकास कार्यों के माध्यम से सार्थक करना उनका दायित्व है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिले का समग्र एवं संतुलित विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और प्रत्येक गांव तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास, सुशासन और

जनकल्याण के नए युग की ओर अग्रसर है। प्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना है। गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

चौधरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिससे गांव और शहर के बीच विकास का अंतर कम हो सके। उन्होंने कहा कि आज जिन कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है, वे केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि क्षेत्र के हजारों लोगों के बेहतर भविष्य की मजबूत आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कें किसी भी क्षेत्र की प्रगति का आधार होती हैं। इससे किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी, विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज जाने में आसानी होगी तथा स्थानीय व्यापार और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। वहीं मिनी स्टेडियम जैसे निर्माण कार्य ग्रामीण युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे। वित्त मंत्री ने 26 करोड़ 80 लाख रुपये से अधिक लागत के चार महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें त्रिभौना-कोड़पाली पहुंच मार्ग पर 2.80 करोड़ रुपये की लागत से 1.50 किलोमीटर सीसी सड़क निर्माण कार्य। मिडमिडा हाईस्कूल पहुंच मार्ग पर 1.24 करोड़ रुपये की लागत से 0.70 किलोमीटर सीसी सड़क निर्माण क मचिदा-कलमी मार्ग पर 3.04 करोड़ रुपये की लागत से 3.50 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य। कोड़ातराई- पुसौर-सूरजगढ़ मार्ग पर 19.71 करोड़ रुपये की लागत से 6.70 किलोमीटर सीसी सड़क निर्माण कार्य। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच और बेहतर बनेगी।

छत्तीसगढ़ में बस सफर जल्द होगा महंगा?

- **परिवहन विभाग और संचालकों की हुई बैठक**

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस यात्रियों के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है जिसमें बस संचालकों ने किराए दरों में वृद्धि को लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही बसों के किराये में वृद्धि की जा सकती है और इसका असर सीधे यात्रियों की जेब पर पडने वाला है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पिछला किराया वृद्धि वर्ष 2021 में की गई थी। डीजल के मूल्य में वृद्धि होने के कारण बस संचालकों ने मांग रखी है कि यात्री किराया डीजल के मूल्य में कमी या वृद्धि के साथ यात्री किराया में भी कमी या वृद्धि का स्थायी कानून बनाया जाए। परिवहन विभाग द्वारा अन्य राज्यों के दरों की तुलनात्मक अध्ययन कर नया किराया दर पर जल्द निर्णय लिया जाए। परिवहन विभाग ने भी महिला व दिव्यांगजन के लिए आरक्षण, कर्मचारी पहचान पत्र, अग्नि सुरक्षा समेत कई बिंदुओं पर चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

परिवहन विभाग द्वारा दिए गए निर्देश

1. प्रत्येक स्टेज कैरिज में क्षमता का 25 प्रतिशत भाग महिला यात्रियों हेतु आरक्षित रहेगा तथा महिलाओं के लिए आरक्षित का बोर्ड स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। प्रत्येक बस में दिव्यांगजनों हेतु न्यूनतम 03 सीटें आरक्षित रखी जाएँ तथा उनके चढने-उतरने हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

2. प्रत्येक यात्री को प्रति पूर्व-मुद्रित टिकट जारी किया जाना अनिवार्य होगा। टिकट में परमिट संख्या, परमिट प्रकार, वाहन क्रमांक, मार्ग, किराया, टिकट क्रमांक, जारी करने की तिथि तथा परिचालक का नाम एवं हस्ताक्षर अंकित रहेंगे। टिकट रिकॉर्ड न्यूनतम 02 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा।

3. प्रत्येक चालक एवं परिचालक को पहचान-पत्र तथा यूनिफॉर्म जारी किया जाना अनिवार्य होगा, जिसमें नाम, पता, फोटो, लाइसेंस, बैज क्रमांक, परमिट विवरण एवं वैधता अंकित रहेगी।

4. वाहन के बाहरी भाग पर स्पष्ट रूप से निम्न जानकारी अंकित की जाए — वाहन स्वामी का नाम एवं पता, मोबाइल नंबर, परमिट संख्या एवं प्रकार, परमिट वैधता, रूट, सेवा विवरण, पुलिस तथा परिवहन हेल्पलाइन नंबर। वाहन के अंदर चालक, परिचालक, परिचय क्रमांक एवं हेल्पलाइन नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएँ।

5. समस्त यात्री बसों, स्लीपर कोच तथा स्कूल बसों में निम्नलिखित सुरक्षा व्यवस्थाएँ कार्यशील स्थिति में उपलब्ध रहना सुनिश्चित किया जाए — आपातकालीन निकास द्वार, आपातकालीन खिड़कियाँ, रूफ एस्केप हैच, आपातकालीन हथौड़े, अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था तथा प्राथमिक उपचार पेटी। किसी भी प्रकार का वेल्डेड स्ट्रक्चर, अवैध पार्टिशन, अतिरिक्त सीट, लगेज अथवा अन्य अवरोध जिससे आपातकालीन निकास बाधित हो, पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

6. एआईएस-119, एआईएस-063 एवं एआईएस-135 के प्रावधानों के अनुसार लागू श्रेणी के वाहनों में आग का पता लगाने और अलार्म प्रणाली तथा आग का पता लगाने और बुझाने की प्रणाली कार्यशील स्थिति में स्थापित होना अनिवार्य होगा।

7. कोई भी बस ऑपरेटर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना वाहन में अवैध बॉडी मॉडिफिकेशन, चेसिस एक्सटेंशन, गैंगवे अवरोध, अनाधिकृत रूपांतरण अथवा अन्य संरचनात्मक संशोधन नहीं करेगा।

8. सभी परमिट धारक निर्धारित परमिट शर्तों, स्वीकृत मार्ग, समय-सारणी, यात्री क्षमता एवं सुरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा यात्री सुरक्षा, सड़क सुरक्षा एवं बस अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम संबंधी जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

10. नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन परमिट धारक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं मोटरयान नियम, 1994 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसमें फिटनेस निलंबन, लाइसेंस निरस्तीकरण, वाहन जब्ती, दंडात्मक कार्यवाही तथा अभियोजन कार्यवाही सम्मिलित हो सकती है।

रायपुर रेल मंडल में जल संरक्षण-ऊर्जा संरक्षण के लिये जागरुकता अभियान

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस अभियान-2026 (15 मई से 5 जून 2026) के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता एवं जन-जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

इसी क्रम में 31मई से 4 जून तक मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर व्यापक जन-जागरूकता एवं निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और संसाधनों के संतुलित उपयोग के साथ भविष्य उन्मुख रेल परिचालन की दिशा में रेलवे के सतत प्रयास किए जा रहे हैं वर्षा जल संचयन सहित जल संरक्षण सिस्टम को बढ़ावा देना। जल पुनर्चक्रण प्रणालियों (एसीडब्ल्यूपी प्रणालियों सहित) का निरीक्षण। जल निकायों का शुद्धिकरण और पुनरुद्धार। उत्पादन इकाइयों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों में जहां भी संभव हो, जल पुनर्चक्रण सुनिश्चित किया जाना। मिशन लाइफ के विषयों के अनुरूप बड़े पैमाने पर नागरिक सहभागिता अभियान। स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय निकायों के साथ सहयोग।ऊर्जा संरक्षण पर जागरूकता अभियान (एलईडी, एसी का इष्टतम उपयोग, उपकरणों को बंद करना)।

जल संरक्षण पर सार्वजनिक अनाउंसमेंट। यात्री समुदायों के साथ जल संरक्षण पहलों में सहभागिता।अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के माध्यम से ई-कचरा जागरूकता और संग्रहण अभियान। जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे स्कूल बी एम वाय भिलाई में क्विज़ प्रतियोगिता कराई गई जिसमें एनवायरमेंट के विषय सम्मिलित किए गए। दुर्ग स्टेशन मे जल संरक्षण हेतु जागरूकता रैली निकाली गयी।

तहसीलदारों के आंदोलन पर गरमाई सियासत

दबाव बनाने के बजाय यह देखें कि लक्ष्मण रेखा किसने लांघी : चंद्राकर

रायपुर। सरगुजा जिले के सीतापुर में नायब तहसीलदार के साथ कथित मारपीट की घटना को लेकर तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर है। इसको लेकर वरिष्ठ बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दबाव के बजाए ये देखना चाहिए कि लक्ष्मण रेखा किसने लांघी।

विधायक अजय चंद्राकर ने अपने बयान में कहा कि यूनियन किस बात की जांच की मांग कर रहा है, स्पष्ट करना चाहिए। हटा देना और कारवाई की मांग करना अलग विषय है। घटना घट क्यों रही ये अलग विषय है। दबाव

के बजाए ये देखना चाहिए कि लक्ष्मण रेखा किसने लांघी। लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि की गरिमा है। उनका सम्मान करना चाहिए।

गौरतलब है कि सरगुजा जिले के सीतापुर में भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों द्वारा नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ कथित मारपीट की घटना के बाद पूरे प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार आक्रोशित हैं। राजस्व अधिकारियों ने शुरुआत में मुख्य आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने सामूहिक अवकाश, कलमबंद हड़ताल और बाद में अनिश्चितकालीन कामबंद आंदोलन शुरू कर दिया।

नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने हसदेव अरण्य को लेकर प्रदर्शन करने की बात कही है, जिसको लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हसदेव अरण्य में भूपेश सरकार ने जो-जो कदम उठाये दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करें। उन्होंने आगे कहा कि अपने शासनकाल में क्या-क्या कदम उठाए, उन्हें सार्वजनिक करने की मांग की जानी चाहिए।

छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना

eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in

निम्नलिखित कार्यों के लिए दिनांक 29.05.2026, 17.30 तक ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है:-

सिस्टिम निविदा क्रमांक	निविदा सूचना क्रमांक एवं दिनांक	कार्य का नाम	निविदा की लागत (लाख में)	आमंत्रण का क्रमांक
191813	01/व.ले.लि./2026-27 दिनांक 29.05.2026	रायगढ़ जिले के विकासखंड लैलूंगा में निर्मित खम्हार-पाकुट जलाशय योजना के मुख्य नहर की आर.डी. 7050 मी. से आर.डी. 8150 मी. तक, कुंजारा माइनर का आर.डी. 0 मी. से आर.डी. 2240 मी. तक व कुंजारा सब माइनर का आर.डी. 0 मी. से आर.डी. 990 मी. तक का सी.सी. लाईनिंग व रिमॉडलिंग कार्य सह 55 नग नहर संरचनाओं का मरम्मत तथा 2 नग हेड्स स्लूस, 2 नग ड्रेनेज कलवर्ट, 1 सुपर-पैसेज, 1 नग क्लोज डक्ट, 7 नग नहर फाल, 41 नग आउटलेट का निर्माण कार्य।	241.61	प्रथम आमंत्रण

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन साइट की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 05.06.2026, समय 17.31 बजे से देखे तथाडाउनलोड किये जा सकते है।

नोट : 1. निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित /पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

2. निविदा की अनुमानित लागत एस.ओ.आर. 01.08.2010 (संशोधित 01.08.2022) के अनुसार है।

कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़ (छ.ग.)
कृते मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन विभाग
बिलासपुर (छ.ग.)

जी-262701095/9

7 सवाल जो खुद टीएमसी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे

सत्येंद्र प्रताप सिंह

ममता बनर्जी जब सड़क पर विरोध करने उतरी थीं, तब आम जनता सीपीएम से त्रस्त व परेशानहाल थी। इसलिए लोगों का भरपूर समर्थन मिला था। अभिषेक बनर्जी जब सड़क पर उतरे तो आम जनता इन्हीं की पार्टी व सरकार से त्रस्त और परेशानहाल होकर निजात पाई थी। ऐसे में जन समर्थन तो दूर विरोध का खुद सामना करना था। सवाल अनगिनत हैं, लेकिन ये सवाल भाजपा सरकार से पहले अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से बनते हैं। दिन में जब अभिषेक बनर्जी बेलेघाटा गए, तब उनके साथ केवल स्थानीय विधायक कुणाल घोष मौजूद थे। कोई अन्य जनप्रतिनिधि या वरिष्ठ नेता उनके साथ नहीं दिखा। वहीं शाम को जब वे सोनारपुर पहुंचे, तब उनके साथ कोई भी नेता नहीं था। आखिर ऐसा क्यों? क्या यह महज संयोग था या इसके पीछे कोई और वजह थी? यह सवाल अब स्वाभाविक रूप से उठ रहा है। दोपहर से ही जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नेताओं को फोन कर कार्यक्रम में मौजूद रहने का अनुरोध किया जाने लगा। लेकिन जिनसे भी संपर्क हुआ, किसी ने खुद को इलाके से बाहर बताया तो किसी ने कोई न कोई कारण बताकर किनारा कर लिया। एक नेता ने तो यहां तक सलाह दे दी कि मौजूदा माहौल को देखते हुए कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर देना ही बेहतर होगा। कई लोगों ने कॉल फॉरवर्डिंग या कॉल डाइवर्ट का सहारा लिया, जबकि कुछ ने अपने फोन ही स्विच ऑफ कर दिए। बताया जाता है कि कई नेताओं को तो अभिषेक बनर्जी ने स्वयं भी फोन किया था। अभिषेक बनर्जी के साथ यह घटना राजपुर सोनारपुर नगरपालिका के वार्ड नंबर 9 में हुई। हैरानी की बात यह है कि 35 वार्डों वाली इस नगरपालिका में तृणमूल कांग्रेस के 34 पार्षद होने के बावजूद, वार्ड नंबर 9 के स्थानीय पार्षद समेत कोई भी पार्षद घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। केवल राजपुर सोनारपुर पंचायत समिति के सभापति बलाईचंद बारीक ही वहां उपस्थित थे। सोनारपुर दक्षिण की पूर्व विधायक लवली मित्रा की अनुपस्थिति भी कई सवाल खड़े करती है। जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में थी, तब अभिषेक बनर्जी के निकट खड़े होने के लिए नेताओं के बीच होड़ लगी रहती थी। ऐसे में इस घटना के दौरान उनकी गैरमौजूदगी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। इस मामले में जिन पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से तीन तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बताए जा रहे हैं। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि ये लोग लवली मित्रा के समर्थक और कार्यकर्ता हैं। यदि यह सही है, तो मामला केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों और गुटबाजी से भी जुड़ा हुआ दिखाई देता है। हादसे के बाद सामने आए वीडियो और तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए गिरफ्तारियां की हैं। उल्लेखनीय है कि इस मामले में न तो अभिषेक बनर्जी और न ही तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। दिलचस्प बात यह है कि राजपुर सोनारपुर नगरपालिका के चेयरमैन पल्लव कुमार दास ने उसी दिन अपराह्न तीन बजे पार्षदों की बैठक बुलाई थी, लेकिन अधिकांश पार्षदों की अनुपस्थिति के कारण बैठक रद्द करनी पड़ी। अभिषेक बनर्जी ने घटना के दौरान जिन लोगों से स्वयं फोन पर संपर्क किया था, उनमें स्थानीय पार्षद अनिता बसु भी शामिल थीं। उस समय अनिता बसु और उनके पति हेमंत बसु अपने घर पर ही मौजूद थे। तृणमूल नेता हेमंत बसु ने अभिषेक बनर्जी से घटनास्थल पर न आने का अनुरोध किया था। उनका कहना था कि इलाके का माहौल अत्यंत तनावपूर्ण है।

गांधी परिवार और भाजपा का वर्चस्व

रामचंद्र गुहा

वर्ष 2024 के आम चुनावों के बाद मेरी मुलाकात कांग्रेस के एक युवा विधायक से हुई। उन्होंने मुझसे राहुल गांधी के लिए पांच सलाहें मांगीं। मैंने कहा कि मेरे पास केवल एक सलाह है-प्रियंका गांधी को वायनाड से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। साथ ही यह भी जोड़ा कि मुझे पूरा विश्वास है, इस सलाह को अनसुना कर दिया जाएगा।

इसमें कोई संदेह नहीं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी विश्वसनीयता बढ़ाई और उन्हें जनता से जुड़े हुए नेता के रूप में स्थापित किया। लेकिन चुनावों के बाद कांग्रेस द्वारा फिर से एक पारिवारिक संस्था की तरह व्यवहार करने से यात्रा से मिले लाभ काफी हद तक बेकार हो गए। प्रियंका गांधी ने वायनाड की सीट जीती-जो उनके लिए उतनी ही सुरक्षित थी, जितनी अमित शाह के लिए गांधीनगर-प्रियंका ने बड़े दावे करते हुए कहा कि वह और उनके भाई देश को जोड़ रहे हैं, वह दक्षिण का प्रतिनिधित्व करती हैं और राहुल उत्तर का। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में हुई बहस के लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मुख्य वक्ता चुना, जबकि दादी ने आपातकाल लगाकर संविधान की भावना को नुकसान पहुंचाया था।

इसी बीच, आम चुनाव में कांग्रेस के 99 सीटें जीतने से राहुल गांधी के आस-पास मौजूद चाटुकारों के समूह को यह प्रचार करने का अवसर मिल गया कि वह अब 'भविष्य के प्रधानमंत्री' हैं। दिल्ली के कुछ बुद्धिजीवियों और पत्रकारों ने इन दावों को बढ़ावा दिया। हिंदुत्व-विरोधी रुख के कारण जिनकी छवि मजबूत मानी जाती थी, उनकी समझदारी शायद सत्ता के पास रहने के आकर्षण के मोह में धुंधली पड़ गई। लेकिन अब साफ दिख रहा है कि वह उत्साह समय से पहले पैदा हुआ था। कांग्रेस की कुछ राज्य इकाइयां, जैसे केरल अब भी संगठित हैं और कभी-कभार विधानसभा चुनाव जीतने की क्षमता रखती हैं, लेकिन देश के अधिकांश हिस्सों में पार्टी लगातार कमजोर होती गई है। राहुल गांधी इस गिरावट को रोक पाने में असफल रहे हैं।

द प्रिंट की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2008 से देश भर में कांग्रेस विधायकों की संख्या लगभग आधी रह गई है-यह 1204 से घटकर 676 पर आ गई है। मैं राहुल गांधी से मिल चुका

भाजपा सरकार को हटाने की सामर्थ्य राहुल और प्रियंका गांधी में नहीं दिखती। सवाल यह है कि जब आर्थिक कुप्रबंधन, बेरोजगारी आदि पर असंतोष चरम पर होगा, तब कौन सा नेतृत्व बदलाव का विश्वास जगा पाएगा?

हूं और पत्राचार भी कर चुका हूं, इसलिए जानता हूं कि वह व्यक्तिगत रूप से एक सज्जन इन्सान हैं। इस सीमित परिचय के बिना भी मुझे उनके प्रति सहानुभूति होती, क्योंकि उन्होंने निजी जीवन में गंभीर त्रासदियां झेली हैं और 55 वर्ष की आयु में भी वह अपनी मां की इच्छा के एक साधन भर बने हुए दिखाई देते हैं। इसमें शायद ही कोई संदेह हो कि उन्होंने सोनिया गांधी के कहने पर राजनीति में प्रवेश किया और उनके कहने पर ही कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं।

राहुल गांधी में अनुशासन, गंभीरता और ठोस अनुभव-तीनों की कमी दिखाई देती है। जब वह किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाते भी हैं, जैसे चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण रवैये का सवाल, तो उसे लगातार और व्यवस्थित तरीके से आगे नहीं बढ़ाते। कभी-कभार 'वोट चोरी' पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और उसके बाद यूरोप या लैटिन अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते हैं। वास्तव में, अपने 22 वर्षों के राजनीतिक जीवन में केवल भारत जोड़ो यात्रा के कुछ महीनों के दौरान ही राहुल गांधी ने ऐसा दिखाया कि वे उस प्रकार का निरंतर और केंद्रित परिश्रम कर सकते हैं, जैसा भाजपा के नेता लगातार करते रहते हैं।

राहुल गांधी में गंभीरता की कमी उनके प्रतीकात्मक और दिखावटी तौर-तरीकों में भी झलकती है। 2004 में सांसद बनने से पहले राहुल गांधी क्या काम करते थे, यह वास्तव में कोई नहीं जानता। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के 10 वर्षों के शासनकाल में भी उन्होंने कभी मंत्री पद स्वीकार नहीं किया। ऐसे में भारतीय मतदाता क्यों भरोसा करें कि वे इतने विशाल, विविधतापूर्ण और चुनौतीपूर्ण भू-राजनीतिक परिस्थितियों वाले देश के प्रभावी प्रधानमंत्री साबित होंगे? राहुल गांधी में अपनी पिछली गलतियों से सीखने की स्पष्ट कमी दिखाई देती है। 2019 में 'चौकीदार चोर है' अभियान बुरी तरह उल्टा पड़ा था, फिर भी वे आज भी प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले करते रहते हैं। कांग्रेस के भीतर बहुत-से लोग इन आलोचनाओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन गांधी परिवार के प्रति आजीवन निष्ठा के कारण उनका मानना है कि अब राहुल की जगह उनकी बहन प्रियंका गांधी को 'भावी प्रधानमंत्री' के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह सही है कि प्रियंका गांधी हिंदी में अपने भाई की तुलना में कहीं बेहतर वक्ता हैं और हिंदी देश के बहुत बड़े हिस्से द्वारा समझी जाती है। लेकिन वे भी वंशवाद से मिलने वाले विशेषाधिकार के बोझ से मुक्त नहीं हैं, बल्कि संभव है कि मतदाताओं को आकर्षित करने में वे अपने भाई से भी कम सफल साबित हों। जिस एकमात्र अवसर पर प्रियंका गांधी ने किसी चुनाव अभियान का नेतृत्व किया-2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में-कांग्रेस का वोट शेयर मात्र 2.27 प्रतिशत रहा।

हाल के विधानसभा चुनावों से एक दिलचस्प और शायद अनदेखा सबक भी मिलता है। मतदाताओं ने वंशवादी राजनीति के प्रति नकारात्मक संकेत दिया। असम में कांग्रेस अभियान का नेतृत्व तरुण गोगोई के बेटे द्वारा किए जाने से भाजपा को लाभ मिला। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा अपने भतीजे अभिषेक को आगे बढ़ाने से भी भाजपा को फायदा हुआ। तमिलनाडु में स्टालिन द्वारा अपने बेटे उदयनिधि को प्रमुखता देने से विजय को मदद मिली, जबकि केरल में विजयन द्वारा अपने दामाद को आगे बढ़ाने का लाभ कांग्रेस को मिला। इसमें कोई संदेह नहीं कि मई 2014 के बाद गणराज्य की इस गिरावट के मुख्य जिम्मेदार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी पार्टी भाजपा हैं। लेकिन अब यह भी उतना ही स्पष्ट हो चुका है कि सत्ता प्राप्त करने और उसे मजबूत बनाए रखने की उनकी कोशिशों में-चाहे जानबूझकर या अनजाने में-सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके आसपास मौजूद चाटुकारों ने भी सहयोगी की भूमिका निभाई है। इस समय मोदी के नेतृत्व में भाजपा अजेय दिखाई देती है। दुर्भाग्य से राहुल या प्रियंका गांधी के बारे में ऐसा कहना कठिन है। यह पूरी तरह संभव है कि आज जो अजेयता का माहौल भाजपा को घेरे हुए है, वह आने वाले वर्षों में टूट जाए। सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्था का शिकार है, नीट घोटाला इसका एक उदाहरण है। केंद्र सरकार की आर्थिक कुप्रबंधन की कीमत अब साफ दिखाई देने लगी है। 2029 के आम चुनाव के करीब आते-आते अधिक हिंदू मतदाता यह समझ सकते हैं कि मुसलमानों के प्रति घृणा फैलाकर महंगाई, सम्मानजनक रोजगार की कमी और अपने बच्चों के असुरक्षित भविष्य जैसी समस्याओं की भरपाई नहीं की जा सकती।

'कॉकरोच जनता पार्टी' के मीम्स की सफलता संकेत देती है कि बहुत-से युवा भारतीय अब सत्तारूढ़ दल के झूठ और प्रचार को समझने लगे हैं। सवाल यह है कि जब यह असंतोष और गहरा होगा, तब कौन इसे एक प्रभावी राजनीतिक चुनौती का रूप देगा? कौन-से नेता देशभर के मतदाताओं को प्रेरित कर पाएंगे। यह संभावना बहुत कम दिखाई देती है कि यह भूमिका राहुल और प्रियंका गांधी निभा पाएं।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

सायराण-माष्योद्धृत-इतिहास

यजुर्वेद भाष्यकार सायणाचार्य ने ऋग्वेद के उपर्युक्त मन्त्रों का व्याख्यान करते हुवे नीचे लिखा इतिहास भी उद्धृत किया है, जिससे इन दोनों मषियों की पुराण-प्रदर्शन उत्पत्ति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है-

तयोरादित्ययो: सत्रे दृष्ट्वाप्सरसमुर्वशीम्।
रेतश्चस्कन्द तत्कुम्भे न्यपतद् वासतीवरे ॥2॥
तेनैव तु मुहूर्तेन वीर्यवन्तौ तपस्विनौ।
अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च तत्रर्षी संबभूवतु: ॥2॥

तात्पर्य प्राय: वही है जो कि वेद मन्त्रार्थ में व्यक्त किया जा का है। आगम प्रमाण की विद्यमानता में हम स्वयं कुछ भी लिखना अनावश्यक समझते हैं, हां इतना इशारा करना अनुचित न होगा कि देवसामर्थ्य की अचिन्त्य महिमा है, तदनुसार वीर्यगत कीटाणुओं का तत्काल प्रवृद्ध हो जाना कुछ दु:साध्य बात नहीं है। यदि इतने पर भी महाशयों को सन्तोष न हो तो उन्हें व्याख्यानभूत पुराण ग्रन्थों का पीछा छोड़ कर वास्तविक अपराधी वेदों अथवा उनके बनाने वाले निराकार बाबा की ही नालिस करनी चाहिये जो कि खुले बन्दो उक्त दोनों महर्षियों की अपाकृतिक उत्पत्ति का ढिंढोरा पीट कर विचारे दयानन्दियों की दकियानूसी का पर्दाफास करते हैं।

सगर के साठ हजार बेटे

ब्रह्माण्ड-पुराण में लिखा है कि सगर की रानी 36 सुमति के गर्भ से एक मांस का बेडौल लौथड़ा पैदा हुआ। राजा उसे बाहिर फेंकने को तैयार था कि महर्षि ओर्व ने उसे समझाया कि इस मांसपिण्ड में बहुत से जीवित बीज विद्यमान हैं, अत: आप यत्नपूर्वक इनकी रक्षा कीजिए जो समय पाकर आपके पुत्र कहलाएँगे। ऋषि की आज्ञानुसार घी के बर्तनों में उस मांसपिण्ड के विभिन्न साठ हजार खण्ड यत्तनपूर्वक रक्खे गये, तथा उनकी रक्षा के निमित्त प्रत्येक बर्तन पर एक 2 धाय नियत कर दी गई। **क्रमशः ...**

विश्व साइकिल दिवस

दिलीप कुमार पाठक

प्रतिवर्ष 3 जून को विश्वभर में विश्व साइकिल दिवस (वर्ल्ड बाइसिकल डे) मनाया जाता है। पाठकों को बताता चलूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 अप्रैल 2018 को एक प्रस्ताव पारित कर 3 जून को विश्व साइकिल दिवस घोषित किया था तथा इस पहल को सफल बनाने में पोलैंड के सामाजिक वैज्ञानिक प्रोफेसर लेशेक सिबिल्स्की तथा उनके विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने समाजशास्त्र के छात्रों के साथ मिलकर विश्व साइकिल दिवस घोषित करने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया तथा उनके सतत प्रयासों और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से

इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। तब से यह दिवस दुनिया भर में उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है।वास्तव में, विश्व साइकिल दिवस को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य साइकिल को एक सरल, सस्ता, विश्वसनीय, पर्यावरण-अनुकूल और स्वास्थ्यवर्धक परिवहन साधन के रूप में बढ़ावा देना है। वास्तव में, यह दिवस लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होने, धरती से कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही यह सड़क सुरक्षा, सस्ती परिवहन व्यवस्था और हरित भविष्य के निर्माण का संदेश भी देता है।

यह दिन किसी आधुनिक आविष्कार का जश्न नहीं, बल्कि उस सादगी और उपयोगिता को याद करने का अवसर है, जिसे हमने विकास की अंधी दौड़ में कहीं पीछे छोड़ दिया है। जब पूरी दुनिया महंगे ईंधन, ट्रैफिक जाम और जहरीले धुएं से हांफ रही है, तब साइकिल एक सुगम साधन की तरह नजर आती है। यह कोई साधारण सवारी नहीं, बल्कि बिना धुएं वाली वह मूक क्रांति है जो व्यक्ति की सेहत, जेब और धरती तीनों को एक साथ संवार सकती है।

आजकल की जीवनशैली को देखें तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। घर से महज दो कदम दूर सब्जी की दुकान या दूध की डेयरी तक जाने के लिए भी लोग तुरंत मोटरसाइकिल या कार की चाबी उठा लेते हैं। नतीजा यह हुआ है कि शहरों की हवा भारी हो चुकी है, सड़कों पर पैदल चलने की जगह नहीं बची और इंसानी शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। लोग शारीरिक रूप से खुद को फिट रखने के लिए हर महीने जिम में हजारों रुपये खर्च करते हैं और एक ही जगह खड़े होकर ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं। जबकि इसका सबसे आसान और प्राकृतिक विकल्प हमारी दिनचर्या में ही छुपा है। सुबह या शाम को सिर्फ आधा घंटा साइकिल चलाना दिल को मजबूत करता है, मानसिक तनाव को कम करता है और शरीर को ऊर्जा से भर देता है।साइकिल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती। इसके लिए न तो महंगे पेट्रोल-डीजल की जरूरत होती है और न ही किसी भारी-भरकम मेंटेनेंस या सर्विसिंग के खर्च की।

अमेरिका-चीन की नजदीकी भारत के लिए बड़ा इम्तिहान

श्याम सरन

अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो की 23 से 26 मई तक की भारत यात्रा में ताजमहल की यात्रा के अलावा दो खास बातें थीं। पहली बात द्विपक्षीय थी यानी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत जबकि दूसरा अवसर था क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में शिरकत करना। यह राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में तीसरी ऐसी बैठक थी। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी क्वाड बैठक से इतर रूबियो के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। ये द्विपक्षीय बैठकें भी बहुपक्षीय बैठकों की तरह ही महत्त्वपूर्ण रहीं। इन बैठकों का क्वाड की बैठक से अलग भी विश्लेषण किया जाना चाहिए।

रूबियो की यात्रा का उद्देश्य साफ तौर पर भारत के साथ रिश्तों में सुधार करना था। बीते एक साल में दोनों देशों के रिश्तों में काफी गिरावट आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए दंडात्मक शुल्क लगाए जबकि उन्होंने चीन, तुर्किये और हंगरी जैसे ऐसा ही करने वाले अन्य देशों को रियायत दी। इसके अलावा वह अक्सर भारत के बारे में अशोभनीय भाषा बोलते हैं। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था तक कहा।

उनकी प्रशासनिक टीम के कई अधिकारियों ने भारत के लिए और भी अधिक अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है और यह 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (मागा) समर्थक समूह के भीतर भी गूंजता रहा है। भारत को ट्रंप के आव्रजन विरोधी अभियान का भी खामियाजा भुगतना पड़ा है, जिसमें एच1-बी वीजा पर प्रतिबंध शामिल हैं जो वर्षों से पेशेवर भारतीयों के लिए करियर में आगे बढ़ने का माध्यम रहे हैं।

पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के साथ अमेरिका की बढ़ती नजदीकी और ईरान के साथ चल रहे युद्ध में मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान को दी गई प्रमुखता ने भारत-पाकिस्तान को एक तराजू पर रखने की

आशंका को फिर से जीवित कर दिया है और इस चिंता को जन्म दिया है कि पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका और चीन दोनों से समर्थन प्राप्त कर सकता है भले ही इन दोनों संरक्षकों के बीच तीव्र टकराव के दिन क्यों न हों। और भी महत्त्वपूर्ण यह संभावना रही है कि अमेरिका और चीन के बीच कुछ हद तक रणनीतिक समायोजन हो सकता है, जिसे ट्रंप की हालिया चीन यात्रा ने और मजबूत किया है। दोनों पक्षों ने रचनात्मक रूप से रणनीतिक टिकाऊपन को आगे बढ़ाने और आर्थिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस सहित कई विवादास्पद मुद्दों पर संवाद में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की।

व्यापार-संबंधी मुद्दों को संभालने के लिए एक व्यापार बोर्ड और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक निवेश बोर्ड की स्थापना, स्पष्ट रूप से परिभाषित मानकों के भीतर, यह दर्शाती है कि चीन से दूरी बनाने के बजाय उससे जुड़े जोखिम कम करना अब अमेरिका की पसंदीदा रणनीति है।

आर्थिक सुरक्षा अब स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है। इससे भारत जैसे देशों के लिए दांव-पेच की गुंजाइश कम हो जाती है। दुनिया की दो सबसे मजबूत शक्तियों के संबंधों में छोटे बदलाव भी अन्य साझेदारों के लिए बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। यही समझ ट्रंप के प्रस्थान के कुछ ही दिनों बाद रूस के राष्ट्रपति की चीन यात्रा को स्पष्ट करती है। यह रूबियो की भारत यात्रा को भी समझाती है जो इसके बाद हुई। अमेरिका और चीन दोनों शक्तियों को अपने सहयोगियों और साझेदारों को यह आश्वस्त करना जरूरी है कि वे अब भी महत्त्वपूर्ण हैं भले ही अमेरिका-चीन संबंधों में बदलाव आया हो।

यात्रा के दौरान बने माहौल और रूबियो द्वारा अपने अनेक सार्वजनिक वक्तव्यों में व्यक्त किए गए गर्मजोशी भरे भावों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सुधार का प्रयास काफी हद तक सफल रहा है और भारत-अमेरिका सहयोग का व्यापक एजेंडा जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद-रोधी क्षेत्र शामिल हैं, निकट भविष्य में अप्रभावित रहेगा। यह भारत के लिए एक सकारात्मक पहलू है। क्वाड की बैठक को भी इसी दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि चीन के साथ रणनीतिक स्थिरता की खोज अमेरिका की हिंद-प्रशांत रणनीति को नहीं बदलती। यदि चीन यह संकेत दे रहा है कि रूस के साथ उसकी असीम साझेदारी अपरिवर्तित है और यूक्रेन युद्ध में रूस को उसका मौन समर्थन जारी है तो अमेरिका के हित में है कि वह यह स्पष्ट करे कि चीन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाई गई उसकी हिंद-प्रशांत रणनीति अब भी लागू है।

यदि वास्तव में कुछ नहीं बदला है, तो अब अपनाई जा रही रणनीतिक स्थिरता की वास्तविक विषय-वस्तु क्या है? इसलिए आश्वासन को स्वीकार करने में तो लाभ है लेकिन भू-राजनीतिक रणनीतिक वातावरण में बड़े बदलाव के प्रति सतर्क रहना भी आवश्यक है। यदि यह बदलाव आगे बढ़ता है तो यह दिए जा रहे आश्वासनों के साथ संगत नहीं होगा।

यह देखना जरूरी होगा कि इस वर्ष ट्रंप और शी चिनफिंग द्वारा आयोजित किए जाने वाले तीन शिखर सम्मेलनों में क्या होता है। इनमें से एक द्विपक्षीय बैठक संभवत: सितंबर में होगी, और अन्य दो आगामी जी-20 तथा एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग बैठकों के दौरान होंगी। ये बैठकें इस बात का स्पष्ट संकेत देंगी कि दोनों पक्ष जिस रणनीतिक स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं उसकी वास्तविक विषय-वस्तु क्या है।

दिल्ली में क्वाड की बैठक महत्त्वपूर्ण है। इसका आयोजन यह दर्शाता है कि अमेरिका चीन को संभालने के संदर्भ में क्वाड का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। क्वाड अमेरिका के लिए एक और सौदेबाजी का साधन बना हुआ है। वैसे ही जैसे चीन के लिए चीन-रूस साझेदारी है। रूबियो ने क्वाड को अपनी हिंद-प्रशांत रणनीति का मुख्य आधार बताया लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रणनीति अब भी मान्य है खासकर ट्रंप-शी चिनफिंग शिखर सम्मेलन में बनी व्यापक सहमति को देखते हुए।

यदि अमेरिका अब क्वाड को केवल एक सौदेबाजी के साधन के रूप में देखता है न कि हिंद-प्रशांत में स्थायी रणनीतिक ढांचे के हिस्से के रूप में, तो इसका बलिदान किया जा सकता है या अधिक संभावना है कि इसे धीरे-धीरे निष्क्रिय होने दिया जाए। ऐसा क्वाड के पहले संस्करण में 2007 में हुआ था जब अमेरिका ने इसे अलग रखने का निर्णय लिया ताकि चीन और रूस की चिंताओं को दूर किया जा सके जिनका समर्थन उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान और उत्तर कोरिया के परमाणु मुद्दों से निपटने के लिए चाहिए था।

अब भी इसी संभावना के प्रति सतर्क रहना चाहिए भले ही भारत के हित में बैठक में घोषित कई व्यावहारिक सहयोग पहलों को आगे बढ़ाया जाए। इन पहलों का मूल्य क्वाड से परे है और इन्हें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी रखा जा सकता है भले ही अमेरिका इसकी महत्ता को कम कर दे।

अंतत: क्वाड का भविष्य अमेरिका की ताइवान की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता से जुड़ा है। यदि अमेरिका ताइवान पर अपनी भाषा बदलता है, जैसे कि वह एक चीन नीति को स्वीकार करता है और ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करता है या एक निश्चित समयसीमा में ताइवान को हथियारों की आपूर्ति कम या बंद कर देता है तो अमेरिका की हिंद-प्रशांत रणनीति का कोई आधार नहीं बचेगा। यह अमेरिका के सहयोगियों विशेषकर जापान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण होगा और भारत के लिए कम। लेकिन इससे क्वाड एक सुरक्षा साझेदारी के रूप में अप्रासंगिक हो जाएगा।

आज का इतिहास

1789 एलेक्स मैकेंज़ी ने मैकेंज़ी नदी (कनाडा) की खोज की।
1828 ग्रान कोलंबिया-पेरू युद्ध में राष्ट्रपति सिमोन बोलिवर ने पेरू पर युद्ध की घोषणा की।
1839 किंग सरकार के अधिकारी लिन ज़ेक्सू ने चीन के हुमेन में लगभग 1.2 मिलियन किलोग्राम (2.6 मिलियन पाउंड) अफीम को नष्ट करने का आदेश देकर प्रथम अफीम युद्ध का आरंभ किया।
1856 क्यूलन व्हिपल ने स्क्रू मशीन का पेटेंट कराया।
1886 युगांडा के नमगोंगो में 24 ईसाइयों को जिंदा जला दिया गया।
1888 अमेरिकी लेखक अर्नेस्ट थायर की बेसबॉल कविता केसी एट द बबट को पहली बार सैन फ्रांसिस्को परीक्षक में प्रकाशित किया गया था।
1915 ब्रिटिश सरकार ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि रविंद्रनाथ टैगोर को 'नाइटहुड' से अलंकृत किया।
1937 एडवर्ड के करीब छह महीने बाद, ड्यूक ऑफ विंडसर ने ब्रिटिश सिंहासन का त्याग कर दिया, उन्होंने फ्रांस के टूर्स के पास एपिकेयर समारोह में अमेरिकी सोशलाइट वालिस सिम्पसन से शादी कर ली।
1940 फ्रेज़ रेडेमैचर, एक नाज़ी सरकारी अधिकारी, ने प्रस्तावित किया कि मेडागास्कर को यहूदियों के यहूदियों के पुनर्वास के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1943 ऑफ-ड्यूटी अमेरिकी नाविकों ने लॉस एंजेलिस में मैक्सिकन अमेरिकी युवाओं के साथ झूट सूट दंगे की लड़ाई लड़ी।
1962 एयर फ्रांस बोइंग-707 विमान पेरिस से उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 130 लोगों की मौत हो गयी।
1963 बौद्ध संकट-दक्षिण वियतनामी सेना के सैनिकों ने हू में बौद्धों पर हमला किया?, आंसू गैसग्रेन से तरल रसायनों के साथ, 67 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
1968 कनाडा ने निकेल के सिक्कों को चांदी में बदलने की घोषणा की।
1968 अमेरिकी कलाकार एंडी वारहोल और दो अन्य को कट्टरपंथी नारीवादी वेलारी सोलानास द्वारा अपने न्यूयॉर्क सिटी स्टूडियो द फैक्ट्री में गोली मारकर घायल कर दिया गया था।
1973 पेरिस एयर शो में, एक टुपोलेव टीयू-144 फ्लाइट के बीच में टूट गया, जिससे चालक दल के छह सदस्य और जमीन पर मौजूद आठबिस्टैंडर्स मारे गए।
1982 यूनाइटेड किंगडम में इजरायल के राजदूत श्लोमो अरगोव पर एक हत्या का प्रयास विफल; बाद में इसे 1982 के लेबनान युद्ध के लिए इस्तेमाल किया गया।

मंत्रियों से चौपाल तक प्रधानमंत्री मोदी की अपील

डॉ. सुयश नारायण मिश्रा

अमेरिका और इजरायल के सैन्य अधिकारी ईरान पर हमले की टारगेट लिस्ट बना रहे हैं। इस प्रकार युद्ध विराम की घोषणा के बाद स्ट्रेट आप होर्मुज के निर्वाध परिवहन पर आशंका की काली घटाएं घिर गयी हैं। लगभग दो महीने पहले अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया था तभी से दुनिया भर में तेल और गैस संकट की शुरूआत हो गयी थी। दुनिया भर में तेल-गैस की राशनिंग के साथ तरह-तरह के प्रतिबंध लगाये गये लेकिन मोदी सरकार ने इस संकट की आंच दो महीने तक जनता तक बिल्कुल नहीं पहुंचने दी। सरकार की अर्थ व्यवस्था अब अतिरिक्त प्रयासों की मांग कर रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता से 10 मई को एक भावुक अपील की थी। इस अपील का प्रभाव मंत्रियों से गांव की चैपालों तक देखा जा रहा है। तेल की बचत करने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सुरक्षा काफिले में वाहन आधे कर दिये गये। कुछ मंत्री तो साइकिल से सचिवालय आते दिखे, वहीं पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए अब गांव-गांव ग्रीन चैपालें लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में 899 ग्राम पंचायतों में 14 मई को एक साथ ग्रीन चैपालें लगाई गयीं। इन चैपालों में लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने पौधारोपण व जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत 10 मई को जनता से जो अपील की है, उसे सामयिक, दूरदर्शी और राष्ट्रहित में माना जाना चाहिए। यह संकट लगभग 11 सप्ताह पूर्व 28 फरवरी से उस समय और गहरा हो गया जब ईरान-इज़रायल युद्ध में अमेरिका कूद पड़ा और ईरान ने दुनिया के सबसे व्यस्त ईंधन मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया। भारत ने ईरान से भी मधुर संबंध बनाए रखे और अमेरिका से भी मित्रता कायम रखी। इससे भारत ने एक तरफ रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा, दूसरी तरफ भारत के तेल और गैस से भरे जहाज होर्मुज के रास्ते ही भारत पहुंच गये। इस बीच ऊर्जा संकट से पूरी दुनिया त्राहि-त्राहि करने लगी और इसकी आंच भारत तक भी पहुंची। मोदी सरकार ने इस अभूतपूर्व ऊर्जा संकट में देश की जनता को संकट का सामना नहीं करने दिया। पूरी दुनिया में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतें आसमान पर पहुंच गयीं लेकिन भारत में चूल्हे भी जलते रहे और वाहन भी चलते रहे। हाँ, तेल और गैस के भंडार अब कम हो रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

ने देश की जागरूक जनता से बहुत सामान्य सहयोग मांगा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और महंगे ईंधन के बीच देशहित में एक अहम अपील की है। उन्होंने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए एक साल तक सोना न खरीदने, खाने के तेल की खपत कम करने, अनावश्यक वाहन उपयोग घटाकर कारपूलिंग करने और विदेश यात्राएं टालने का आग्रह किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा, देशभक्ति सिर्फ जान देना नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में ज़िम्मेदारी से जीना भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील की।

पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम करने पर ज़ोर दिया। इसके पीछे सीधा हिसाब है। दफ्तर आने-जाने में रोज़ाना लाखों लीटर पेट्रोल-डीजल जलता है। कॉर्पोरेट कंपनियाँ अगर हफ्ते में कुछ दिन भी वर्क फ्रॉम होम लागू करें तो ईंधन की खपत और आयात का बोझ दोनों कम हो सकते हैं। पीएम ने नागरिकों से अपील की है कि वे गैर जरूरी विदेश यात्रा, विदेश में छुट्टियां मनाने और विदेशी शादियों से बचकर और घरेलू पर्यटन और भारत के भीतर समारोह आयोजित करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करें।

पीएम मोदी ने लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश है और हम हर साल करीब 59 अरब डॉलर यानी लगभग पांच लाख करोड़ रुपए का सोना बाहर से मंगाते हैं। सोने की कीमत और रुपए की कमजोरी के बीच सीधा रिश्ता है। सोना महंगा होता है तो रुपया और टूटता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों को मेड-इन-इंडिया और लोकल लेवल पर बनने वाले प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया, जिनमें जूते, बैग और सहायक उपकरण जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं। भारतीय सामान खरीदने से आयात कम होगा और देश के उद्योग और रोज़गार को फायदा मिलेगा।

पीएम मोदी ने किसानों से अपील कि वे रासायनिक खाद का उपयोग 50 प्रतिशत कम करें, प्राकृतिक खेती अपनाएं और डीजल पंप की जगह सौर पंप लगाएं। भारत यूरिया की अपनी ज़रूरत का 25 प्रतिशत, फास्फेट का 90 प्रतिशत और पोटाश का पूरा 100 प्रतिशत विदेश से मंगाता है। 2023-24 में सिर्फ उर्वरक सब्सिडी का बोझ 1.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यूरिया बनाने के लिए प्राकृतिक गैस चाहिए जो खुद आयात होती है। पश्चिम एशिया संकट में गैस महंगी हुई तो खाद महंगी हुई और सरकार की सब्सिडी और बढ़ी। खाद का इस्तेमाल कम करें तो यह पूरी चेन टूटती है।

वैश्विक ऊर्जा मार्ग स्ट्रेट आफ होर्मुज से प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल का परिवहन होता है। जहाजों का आवागमन बंद होने से इस वैश्विक संकट का प्रभाव अभूतपूर्व रहा। ब्रेंट क्रूड की कीमत 70 डॉलर से बढ़कर 126 डालर प्रति बैरल हो गयी है। इसके परिणामस्वरूप दुनिया के कई देशों को असाधारण कदम उठाने पड़े। बांग्लादेश में ईंधन की राशनिंग हुई। श्रीलंका में चार दिवसीय कार्य सप्ताह के साथ फ्यूल पास जारी किये गये हैं। दक्षिण कोरिया ने पहली बार ईंधन मूल्य सीमा तय की है। जापान को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक तेल भंडार उपयोग करना पड़ रहा है। भारत का लगभग 40 फीसद तेल आयात खाड़ी देशों से होता है। इस प्रकार हमारे देश को भी अभूतपूर्व ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा। भारत सरकार ने अब दो महीने बाद देश की जनता से अपना योगदान देने के लिए अपील की है जो देश-हित में है।

भरोसे की परीक्षा: फौरी कदमों से नहीं बनेगी बात

पवन

नीट-यूजी के प्रश्नपत्र लीक होने और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में कथित गड़बड़ियों को लेकर उठा विवाद अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली देश की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) में आई तकनीकी समस्याओं के मद्देनजर देश का परीक्षा-तंत्र गंभीर चुनौतियों और विश्वसनीयता के संकट से जूझता दिखाई दे रहा है।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने बेशक बाद में खेद जताते हुए कहा है कि बायोमीट्रिक करा चुके छात्र, जो किन्हीं वजहों से नीट-यूजी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा, लेकिन इससे छात्रों को जो दिक्कतें हुईं, उससे परीक्षा प्रणाली पर सवाल तो उठते ही हैं। किसी भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की विश्वसनीयता उसकी पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुचारू संचालन से तय होती है। जब लाखों अभ्यर्थी वर्षों की मेहनत, समय और संसाधन लगाकर किसी परीक्षा में शामिल होते हैं, तब यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे प्रशासनिक चूक, तकनीकी अव्यवस्था या संस्थागत लापरवाही की कीमत चुकाएं। देश की इन बड़ी परीक्षाओं में बार-बार हो रही चूकें ये संकेत देती हैं कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी तकनीक पर तो तेजी से निर्भर हो रही है, लेकिन उस तकनीक को निर्बाध और भरोसेमंद बनाने के लिए आवश्यक तैयारी और बुनियादी ढांचे पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा। इन घटनाओं का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव छात्रों के मनोबल पर पड़ता है। एक ऐसा विद्यार्थी, जिसने कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच

सफलता पाने के लिए दिन-रात मेहनत की हो, उसके लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं होता कि उसकी परीक्षा किसी ऐसी खामी से प्रभावित हो गई, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था।

एनटीए की स्थापना ही इस उद्देश्य से की गई थी कि देश की प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और त्रुटिरहित ढंग से आयोजित किया जा सके। लेकिन हाल के वर्षों में जिस तरह बार-बार विवाद सामने आए हैं, उन्होंने इस संस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जवाबदेही तय करने और संघ लोक सेवा आयोग से सीख लेने की जो बात की है, वह बिल्कुल जायज है।

यह सवाल भी जवाब की मांग करता है कि जब राधाकृष्णन समिति ने अक्तूबर, 2024 में एनटीए की प्रक्रियाओं में सुधार सुझाए थे, तो अब तक उन पर पूरी तरह से अमल क्यों नहीं हो पाया। यह करोड़ों युवाओं की आकांक्षाओं और भविष्य से जुड़ा संवेदनशील विषय है। इसलिए, जरूरत केवल फौरी कदमों की नहीं, बल्कि व्यापक संस्थागत सुधारों की भी है। आखिर सरकार और परीक्षा एजेंसियां मिलकर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनातीं, जिसमें छात्रों की मेहनत ही सफलता का एकमात्र आधार हो और किसी तकनीकी या प्रशासनिक विफलता की कोई गुंजाइश ही न बचे।

सत्ता की ठसक से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ममता-अभिषेक

सत्येंद्र प्रताप सिंह

सत्ता जाने के बाद भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के व्यवहार में सत्ता की ठसक साफ दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी आज भी सोशल मीडिया पर अपने नाम के साथ पूर्व मुख्यमंत्री लिखने को तैयार नहीं हैं। उनके फेसबुक और एक्स हैंडल पर अब भी 15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा की मुख्यमंत्री लिखा हुआ है। इससे यही प्रतीत होता है कि वे विधानसभा चुनाव के परिणामों को सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रही हैं।

दूसरी ओर, अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक की नियुक्ति संबंधी एक पत्र विधानसभा अध्यक्ष को भेजा। विधानसभा अध्यक्ष ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब तृणमूल कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई, तो विधानसभा अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि पार्टी के महासचिव किस अधिकार से यह प्रस्ताव भेज रहे हैं। उन्होंने पूछा कि जिन विधायकों ने इन नेताओं का चयन किया है, उनके हस्ताक्षर कहां हैं?

इसके बाद नामित नेता प्रतिपक्ष शोभनदेव चट्टोपाध्याय, नामित उपनेता असीमा पात्रा व नयना बंदोपाध्याय, नामित मुख्य सचेतक फिरहाद हकीम और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कुणाल घोष कुछ विधायकों के साथ विधानसभा परिसर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। वे विधानसभा अध्यक्ष से मिलने की मांग करते हुए कई बार उनके कक्ष के बाहर भी पहुंचे, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा।

जब विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों के हस्ताक्षरयुक्त प्रस्ताव की मांग की, तब 6 मई की उसी चिट्ठी को दोबारा भेजा गया, जिस पर बाद में 19 मई को विधायकों के हस्ताक्षर कराए गए। आरोप यह भी है कि इस पत्र पर कुछ ऐसे विधायकों के हस्ताक्षर मौजूद हैं, जो 6 मई की बैठक में शामिल ही नहीं थे। जैसे, कैनिंग पूर्व विधानसभा सीट से विधायक मोहम्मद बहरुल इस्लाम। ऐसे कई विधायक हैं जो 6 मई की बैठक में नहीं थे लेकिन उनके हस्ताक्षर पत्र में हैं। पूरी घटना को सिलसिलेवार समझते हैं। 4 मई को मतगणना होती है व ममता बनर्जी की सत्ता का अंत

होता है। 6 मई को टीएमसी विधायक दल की बैठक होती है, ममता बनर्जी स्वयं पार्टी का नेता, उप नेता और मुख्य सचेतक चुन देती हैं। अभिषेक बनर्जी उसके बाद इससे सम्बंधित पत्र विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय को भेज देते हैं। राजनीति अब यहीं से करवट लेती दिख रही है। चुनावी पराजय के बाद जहां तृणमूल कांग्रेस विद्रोह और पलायन की समस्या से जूझ रही थी, वहीं अब वह हस्ताक्षर विवाद के संकट में फंसती नजर आ रही है। कुछ विधायकों के हस्ताक्षरों में असमानता की शिकायत मिलने के बाद विधानसभा की ओर से कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने सीआईडी की मदद से जांच शुरू कर दी है।

हस्ताक्षरों की सत्यता परखने के लिए सीआईडी की टीम हस्ताक्षर विशेषज्ञ (हैंडराइटिंग एक्सपर्ट) और वीडियोग्राफर के साथ कई टीएमसी विधायकों के घर पहुंची। टीम ने चौरंगी की विधायक नयना बंदोपाध्याय, बेलेघाटा के विधायक कुणाल घोष, कैनिंग पूर्व के विधायक मोहम्मद बहरुल इस्लाम और डोमजूर के विधायक तापस माइती से पूछताछ की। बोलपुर के विधायक चंद्रनाथ सिन्हा के घर भी टीम पहुंची, हालांकि इसकी स्पष्ट वजह सामने नहीं आई।

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के एक प्रस्ताव पर 80 में से 70 विधायकों के हस्ताक्षर होने का दावा किया गया है। अब उन्हीं हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। जब कुछ तृणमूल कांग्रेस के विधायक स्वयं कह रहे हैं कि उन्होंने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो फिर सवाल उठता है कि वे हस्ताक्षर किसने किए? विवाद की शुरुआत कैनिंग पूर्व के विधायक मोहम्मद बहरुल इस्लाम के हस्ताक्षर को लेकर हुई। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने तक वह इस मामले पर अधिक टिप्पणी नहीं करेंगे। उनके अनुसार जांच अधिकारियों ने उनसे पूछा कि 6 मई को वह कहां थे। उन्होंने बताया कि उस दिन वह अपने घर भांगड़ में थे। उन्हें एक बैठक से संबंधित हस्ताक्षर दिखाया गया, जबकि उनका कहना है कि वह उस दिन किसी बैठक में शामिल नहीं हुए थे और चुनाव बाद हुई हिंसा के कारण घर पर ही थे। सीआईडी की टीम चौरंगी की विधायक और नामित उपनेता नयना बंदोपाध्याय के घर भी काफी देर तक रही। नयना बंदोपाध्याय ने बताया कि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई है। उनका कहना था कि यह कोई विधानसभा का दस्तावेज नहीं, बल्कि पार्टी का दस्तावेज है। उनके अनुसार पार्टी ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया था और उन्होंने उस कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे क्योंकि वहां पर्याप्त जगह नहीं थी।

वहीं, नामित नेता प्रतिपक्ष और बालीगंज के विधायक शोभनदेब चटर्जी ने आरोप लगाया कि विधायकों को अनावश्यक रूप से परेशान और भयभीत किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि नयना बंदोपाध्याय ने हस्ताक्षर किए थे, बावजूद इसके उनसे कहा गया कि हस्ताक्षर उनके नहीं हैं। जांच अधिकारी उनका पैन कार्ड का फोटो भी लेकर गए। दिलचस्प बात यह है कि नयना बंदोपाध्याय द्वारा विधायक पद की शपथ लेने के बाद किए गए आधिकारिक हस्ताक्षर और विवादित प्रस्ताव पर मौजूद हस्ताक्षर में समानता नहीं पाई जा रही है। ऐसे में अब सबकी नजर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर टिकी है, जो इस विवाद की दिशा तय कर सकती है। फिलहाल कोलकाता पुलिस और सीआईडी मामले की जांच में जुटी हैं। रिपोर्ट आने और आगे की कार्रवाई शुरू होने के बाद यह विवाद अदालत तक पहुंच सकता है। अदालती प्रक्रिया और विधानसभा अध्यक्ष के संवैधानिक अधिकारों को देखते हुए इतना स्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक चुनौतियों का दौर अभी समाप्त होता नहीं दिख रहा।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खेल से पाकिस्तान की जान सूखी!

विकास मिश्रा

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कूटनीतिक स्तर पर अचानक ऐसी चाल चल दी है कि न केवल महारथी अमेरिका हैरत में है बल्कि उसके प्यारे दुलारे पाकिस्तान की तो जान ही सूखी जा रही है। अफगानिस्तान और रूस के बीच एक डिफेंस डील हुई है जिसमें हथियारों का आदान-प्रदान, लाइसेंसिंग, सैन्य तकनीकें और संयुक्त विकास परियोजनाएं शामिल हैं। मॉस्को में हुए समझौते में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब और रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने हस्ताक्षर किए। माना जा रहा है कि इस डिफेंस डील के व्यापक परिणाम होने वाले हैं।

इससे तालिबान शक्तिशाली होगा और रूस भी फायदे में रहेगा। रूस एकमात्र देश है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता दी हुई है। अप्रैल 2025 में रूसी सर्वोच्च न्यायालय ने तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा दिया था। इसके बाद दोनों देशों ने राजदूतों की नियुक्ति की। हालांकि रूस वही देश है जिसने अफगानिस्तान पर हमला करने के बाद वहां दस साल तक शासन किया और अंततः उसे वहां से भागना पड़ा था। फिर अमेरिका ने भी करीब 20 साल अफगानिस्तान पर कब्जा जमाए रखा लेकिन उसे भी भागना पड़ा।

रूस को मुजाहिदीनों ने भगाया तो अमेरिका को तालिबान ने। अभी तक रूस के अलावा किसी देश ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है लेकिन कई देशों ने कामकाजी संपर्क बना रखा है। मानवीय स्तर पर भारत का भी संबंध तालिबान से है। अफगानी लोग भारत को बहुत सम्मान के साथ देखते हैं। वहां के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने पिछले साल भारत की यात्रा भी की थी जिसे लेकर पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी थी। कारण यह है कि अमेरिका के जाने के बाद जब तालिबान सत्ता में आया तो पाकिस्तान को पूरा भरोसा था कि तालिबान उसकी गोद में खेलेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तालिबान को स्पष्ट तौर पर महसूस हुआ कि पाकिस्तान दगाबाज देश है और वह भविष्य के लिए खतरा उत्पन्न करेगा।

हाल के दिनों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कई झड़पें भी हुई हैं। पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले भी किए हैं। ऐसी स्थिति में तालिबान को महसूस होता रहा है

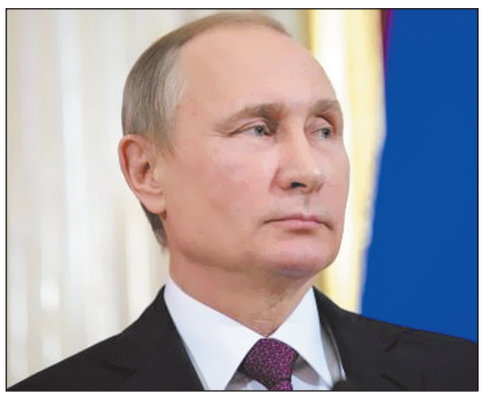

कि उसके पास अमेरिका के छोड़े हुए हथियार तो बहुत से हैं लेकिन उसकी मरम्मत और संचालन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा उसे नए हथियार भी चाहिए ताकि वह पाकिस्तान जैसे देश का मुकाबला कर सके।

इसलिए तालिबान इस कोशिश में लगा था कि रूस के साथ उसकी डीफेंस डील हो जाए। इधर यूक्रेन से लगातार जारी जंग के बीच रूस सैनिकों की कमी महसूस करता रहा है। ऐसी खबरें भी आईं कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस की ओर से यूक्रेन से जंग लड़ रहे हैं। अब इस डील के बाद सवाल सामने है कि क्या रूसी हथियारों के बदले तालिबान के लड़ाके यूक्रेन से लड़ने जाएंगे?

डिफेंस डील को दोनों ही देशों ने सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। रूस फिलहाल आर्थिक रूप से इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है कि फोकट में अफगानिस्तान को हथियार और नई टेक्नोलॉजी दे सके। अफगानिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वह हथियार खरीद सके। ऐसी स्थिति में दोनों देश क्या बार्टर सिस्टम पर काम कर सकते हैं?

यानी रूस तालिबान को हथियार दे और तालिबान रूस को लड़ाके उपलब्ध कराए? कूटनीति में कुछ भी संभव है। इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता। बार्टर सिस्टम की बदौलत रूस को लड़ाके मिल जाएंगे और तालिबान को हथियार मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि तालिबान मजबूत होगा तो सबसे बड़ी परेशानी पाकिस्तान को ही होने वाली है। इस डिफेंस डील के माध्यम से तालिबान को शक्तिशाली बनाने की चाहत रूस की भी रही है। रूस की चिंता इस बात को लेकर भी ज्यादा रही है कि इस्लामिक स्टेट व अन्य कट्टरपंथी ताकतें वहां अपने फन फैलाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि इस्लामिक स्टेट पर काबू पाने की हर संभव कोशिश तालिबान करता रहा है लेकिन अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में इस्लामिक स्टेट का वजूद मजबूत हो रहा है।

ऐसा आकलन है कि अफगानिस्तान में 20 से ज्यादा गुटों के करीब 10 हजार आतंकी मौजूद हैं। इस्लामिक स्टेट के साथ ही अन्य हथियारबंद गुटों की मदद पाकिस्तान कर रहा है ताकि तालिबान की ताकत को तोड़ा जा सके। यदि इस्लामिक स्टेट और अन्य गुटों का प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ता है और यदि इनका राज वहां आ गया तो स्वाभाविक रूप से वह न केवल रूस बल्कि भारत के लिए भी खतरनाक होगा।

इसके अलावा चीन भी नहीं चाहेगा कि इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान में आकर बैठ जाए। इसलिए सारी ताकतें चाहती हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत रहे। दुनिया को पता है कि तालिबान को केवल अफगानिस्तान से मतलब है या फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कुछ हिस्से उसे चाहिए जिसे वह अपना मानता है। इसके अलावा कहां क्या हो रहा है, उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता!

इसके विपरीत इस्लामिक स्टेट का एजेंडा दुनिया भर में शरिया शासन लागू करना है। वह दुनिया को इस्लाम की चादर में लपेटना चाहता है। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट का बढ़ना निश्चय ही भारत के लिए भी चिंता की बात होगी। इसलिए हम यह मान सकते हैं कि इस डील से भारत भी फायदे में है।

इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ डिफेंस डील से रूस का पश्चिम विरोधी गठबंधन को सशक्त करने का सपना भी साकार होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की चाहत रही है कि कम से कम एक अमेरिकी मिलिट्री बेस तो अफगानिस्तान में होना ही चाहिए। मगर रूस और तालिबान, दोनों ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का कोई भी मिलिट्री बेस नहीं बनने दिया जाएगा। यानी इस डील से अमेरिका को भी चोट पहुंची है। यदि अमेरिका कोई कोशिश करेगा तो उसे सीधे रूस का सामना वहां करना पड़ेगा। इस डील से अफगानिस्तान को यह दावा करने का मौका मिलेगा कि वह अब अलग-थलग नहीं है।

अमेरिकी दबाव के बीच बदलता पश्चिम एशिया का शक्ति संतुलन

कांतिलाल मांडोत

पश्चिम एशिया एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। हाल के दिनों में ईरान द्वारा अमेरिकी एमक्यू-1 ड्रोन को मार गिराने का दावा, होर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ती सैन्य गतिविधियां, लेबनान में संघर्ष और परमाणु समझौते को लेकर चल रही कूटनीतिक खींचतान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह केवल दो देशों के बीच का विवाद नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का मामला बन चुका है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का यह दावा कि ईरान परमाणु हथियार न बनाने और न खरीदने पर सहमत हो गया है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म देता है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि अमेरिका का दबाव काम कर रहा है और ईरान पीछे हट रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। ईरान ने यदि परमाणु हथियारों के निर्माण से दूरी बनाने की बात स्वीकार भी की है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी सामरिक या सैन्य शक्ति कमजोर हो गई है। पिछले दो दशकों में ईरान ने अपनी रक्षा नीति को इस प्रकार विकसित किया है कि वह बिना परमाणु हथियारों के भी क्षेत्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली शक्ति बना रहे। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल क्षमता है। उसके पास हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं, जो पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल जैसे देशों के लिए लगातार चुनौती बनी हुई हैं। इसके अलावा ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में भी ईरान ने उल्लेखनीय प्रगति की है। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरानी ड्रोन की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। आज ईरान कम लागत में बड़ी संख्या में ऐसे ड्रोन तैयार करने में सक्षम है जो युद्ध के मैदान में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। ईरान की एक और बड़ी ताकत उसके क्षेत्रीय सहयोगी समूह हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती संगठन, इराक और सीरिया में सक्रिय कई सशस्त्र समूह ईरान के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा माने जाते हैं। यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान के साथ किसी भी संभावित संघर्ष का अर्थ केवल एक देश से युद्ध नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में कई मोर्चों पर संघर्ष हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका की सैन्य शक्ति अत्यधिक मजबूत होने के बावजूद वह प्रत्यक्ष युद्ध को लेकर सावधानी बरतता दिखाई देता है। अमेरिका ने लंबे समय से ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों, राजनीतिक दबाव और सैन्य चेतावनियों की नीति अपनाई है। उसका उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना और क्षेत्र में उसके प्रभाव को सीमित करना रहा है। लेकिन बीते वर्षों के अनुभव बताते हैं कि केवल दबाव की नीति से अमेरिका अपने सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अपनी सैन्य क्षमताओं को विकसित किया और क्षेत्रीय राजनीति में अपनी मौजूदगी बनाए रखी। डोनाल्ड ट्रम्प के हालिया बयान भी इसी द्वंद्व को दर्शाते हैं। एक तरफ वे कहते हैं कि अमेरिका अपनी शर्तें मनवा रहा है और दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि उन्हें समझौते की कोई जल्दी नहीं है। यह बयान बताता है कि वाशिंगटन अभी भी दबाव और कूटनीति दोनों रास्तों को साथ लेकर चलना चाहता है। यदि अमेरिका पूरी तरह आश्वस्त होता कि वह सैन्य कार्रवाई के जरिए अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है, तो शायद वह समझौते की भाषा पर इतना जोर नहीं देता। कई विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में अमेरिका भी कुछ हद तक बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। इसका कारण केवल ईरान की सैन्य शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक परिस्थितियां भी हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध, चीन के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा, वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और ऊर्जा बाजार की अनिश्चितता अमेरिका को एक और बड़े युद्ध से बचने के लिए प्रेरित करती हैं।

आज के भागदौड़ और थकाने वाले जमाने में छात्रों की पूरी दिनचर्या बदल गई है। तनाव हावी होता है और भूख कम लगती है। कैफीनयुक्त चीजें व जंक फूड का सेवन बढ़ जाता है। वजन बढ़ने के साथ-साथ कुछ में इसका असर याद करने की क्षमता पर भी दिखाई देता है। याद किए हुए को याद रख पाने के लिए छह से सात घंटे की नींद जरूरी होती है, तो बेचैनी को कम करने के लिए ताजी हवा और पर्याप्त पोषण की। हमारे शरीर के कुल वजन का 2 वजन रखने वाला हमारा मस्तिष्क पूरे शरीर की 20 ऑक्सीजन और कैलोरी का इस्तेमाल करता है। पूरे दिन घर के भीतर किताब और लैपटॉप में समय बीतने के कारण पॉस्चर में आने वाला बदलाव फेफड़ों की क्षमता और ऑक्सीजन के स्तर को कम करता है, जिससे उलझन, याद न रख पाने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

वो खाएं जो याददाश्त बढ़ाए

दिमाग की जरूरत को समझें

कई शोध साबित करते हैं कि किस तरह पर्याप्त पोषण मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाता है। यहां तक कि कुछ समय के लिए हुई पोषण की कमी भी मस्तिष्कीय कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा देती है और मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स की क्षमता को कम करती है। अक्सर छात्र कुछ भी आसानी से उपलब्ध हो जाने वाली खाने की तली-भुनी चीजें खाने लगते हैं। कैफीनयुक्त चीजों का सेवन बढ़ जाता है और शारीरिक सक्रियता कम हो जाती है। विटामिन ए, ई और सी जैसे एंटीऑक्सी डेंट्स से भरपूर खाने की चीजें मस्तिष्क की कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को रोकती हैं। विटामिन ए के लिए गाजर, ब्रोकली, मेवे और चने खाने चाहिए। विटामिन सी के लिए खट्टे फल जैसे संतरे, नींबू, मौसमी और विटामिन ई के लिए मूंगफली, पालक, वनस्पति घी आदि ले सकते हैं।

पालक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जिसमें बीटा केरोटीन, विटामिन सी और फॉलिक एसिड होता है, जिससे मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र प्रभावी ढंग से काम करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर मस्तिष्क तक ऑक्सीजन की पूर्ति में कमी आती है। इसके लिए भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, तिल, बींस, मछली, डेयरी उत्पाद व रेड मीट आदि नियमित खाने चाहिए। अगर शरीर में आयरन की कमी है तो चिकित्सक की सलाह से आयरन, विटामिन बी-12 व फॉलेट सप्लीमेंट्स ले सकते हैं।

खाली पेट चाय पीने के ये हैं नुकसान

चाय भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग बन चुकी है, जिसे हम चाह कर भी नजर अंदाज नहीं कर सकते। जिस दिन चाय ना पियों तो ऐसा लगता है मानों दिन की शुरुआत ही नहीं हुई है। भारत में लगभग 90 प्रतिशत लोग सुबह नाश्ते से पहले चाय जरुर पीते हैं। क्या आपको लगता है कि यह एक अच्छी आदत है? रिसर्च के अनुसार सुबह खाली पेट चाय पीना काफी नुकसानदायक हो सकता है, खासतौर पर गर्मियों में। चाय में कैफीन और टैनिन होते हैं जो कि शरीर में ऊर्जा भर देते हैं। काली चाय में अगर दूध मिला कर पिया जाए तो इससे एंटीऑक्सीडेंट खतम हो जाता है और फिर वह उतनी असरदार नहीं होती।

चाय पीने के फायदे भी अधिक हैं

- क्या आप का चाय पिये बिना काम नहीं चलता ? अगर ऐसा है तो चाय के बारे में कुछ जरुरी जानकारी है जो हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। अगर आप खाली पेट या फिर अधिक चाय पीते हैं तो आपको इसके नुकसान के बारे में जरुर पता होना चाहिए।
- क्या चाय पी कर मतली आती है चाय में ढेर सारा एसिड होता है जिसे खाली पेट सुबह पीने से पेट के रस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कई लोगों को सुबह चाय पीनी अच्छी नहीं लगती।
- क्या ब्लैक टी नुकसानदेह है अगर चाय में दूध ना मिलाया जाए तो वह काफी फायदा पहुंचाती है, जैसे मोटापा कम करना। पर अगर अधिक ब्लैक टी का सेवन किया जाए तो वह सीधे पेट पर असर करती है।
- दूध की चाय पीने के नुकसान अध्यन के अनुसार पाया गया है कि जो लोग खाली पेट बहुत अधिक दूध वाली चाय पीते हैं, उन्हें थकान का एहसास होता है। चाय में दूध मिलाने से एंटीऑक्सीडेंट का असर खतम हो जाता है।
- कड़ी चााय पीने के प्रभाव खाली पेट कड़ी चाय पीन से पेट को सीधा नुकसान पहुंच सकता है। कड़ी चाय से पेट में अल्सर और एसिडिटी हो सकती है।
- दो अलग-अलग चाय मिला कर पीने का नुकसान अध्यन के अनुसार पता चला है कि अगर आप दो अलग अलग ब्रैंड की चाय एक साथ मिला कर पियेंगे तो उसका असर काफी तेज होगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप नशा चढ़ चुका है।
- चाय के साथ बिस्कुट खाने से क्या होता है चाय के साथ बिस्कुट या अन्य चीजें खाने से पेट द्वारा चाय अच्छी तरह से पचा ली जाती है। दूसरी ओर चाय के साथ नमकीन या मीठा खाने से शरीर को सोडियम की प्राप्ती होती है, जिससे अल्सर नहीं होता।
- चााय पीने की गंदी आदत क्या है चाय में टैनिन होता है, खासतौर पर गहरे रंग वाली चाय में। ऐसे में वह आपके खाने में मौजूद आयरन के साथ रिएक्ट कर सकती है इसलिये दोपहर में खाना खाने के बाद चाय ना पिएं।
- प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ता है जो पुरुष दिन में 5-कप चाय पीते हैं, उन्हें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ता है, ऐसी बात एक अध्यन में आई है। इससे पहले कई शोधो में दावा किया गया है कि चाय पीने से कैंसर का खतरा टलता है।

हर मामले में जरूरी नहीं जोड़ प्रत्यारोपण

गठिया एक ऐसी बीमारी है, जो उम्र बढ़ने के साथ किसी भी व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकती है। खासकर मिडिल एज के लोगों और वृद्धजनों को गठिया की समस्या कुछ ज्यादा ही प्रभावित करती है। यह सच है कि जोड़ प्रत्यारोपण उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों के क्षतिग्रस्त हुए कार्टिलेज की समस्या के दूर करने का कारगर व सुरक्षित उपचार है, लेकिन हर मामले में जोड़-प्रत्यारोपण की जरूरत नहीं होती। इसलिए जोड़ प्रत्यारोपण के अन्य विकल्पों के बारे में भी जानना जरूरी है।

पहला विकल्प : गठिया की शुरुआती स्थिति में फिजियोथेरेपी और कई प्रकार की दवाएं दी जाती हैं। ये दवाएं मरीज को राहत दिलाने के साथ-साथ मर्ज को बढ़ने से भी रोकती हैं।

दूसरा विकल्प : इंट्रा आर्टीकुलर इंजेक्शन दूसरा विकल्प है। इस विकल्प के अंतर्गत विभिन्न तरह की दवाएं इंजेक्शन के जरिए दी जाती हैं। ये दवाएं मरीज को गठिया से राहत दिलाने में मददगार होती हैं।

तीसरा विकल्प : आर्थोस्कोपिक सर्जरी के जरिए दूरबीन विधि द्वारा गठियाग्रस्त जोड़ को दर्द रहित और गतिशील बनाया जा सकता है।

चौथा विकल्प : इसके अंतर्गत ऑस्टियोटॉमी को शुमार किया जाता है। क्षतिग्रस्त जोड़ को ऑस्टियोटॉमी विधि के जरिए जोड़ के विभिन्न भागों में पडने वाले दबावों को स्थानांतरित करके गठिया के दर्द से राहत पाई जा सकती है।

पांचवा विकल्प : इस विकल्प के अंतर्गत आंशिक प्रत्यारोपण किया जाता है। जब जोड़ का सिर्फ कुछ भाग ही क्षतिग्रस्त है, तब पूर्ण प्रत्यारोपण की बजाय आंशिक प्रत्यारोपण से भी अनेक मरीजों को राहत मिल सकती है।

डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी दुनियाभर में फैली है। हर 5में से 4 लोग इस बीमारी का शिकार हैं। वहीं भारत में तो यह बीमारी सबसे बड़ा गढ़ बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारा लाइफस्टाइल है। अगर खाने-पीने की आदतों को थोड़ा सुधार लिया जाए तो काफी हद तक इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि खाली पेट सुबह सबसे पहले अपना शुगर लेवल चेक करें और रात को सोते समय भी अपना शुगर लेवल चेक कर लें क्योंकि इसकी मदद से आप उसी तरह की डाइट ले सकते हैं।

डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के तरीके

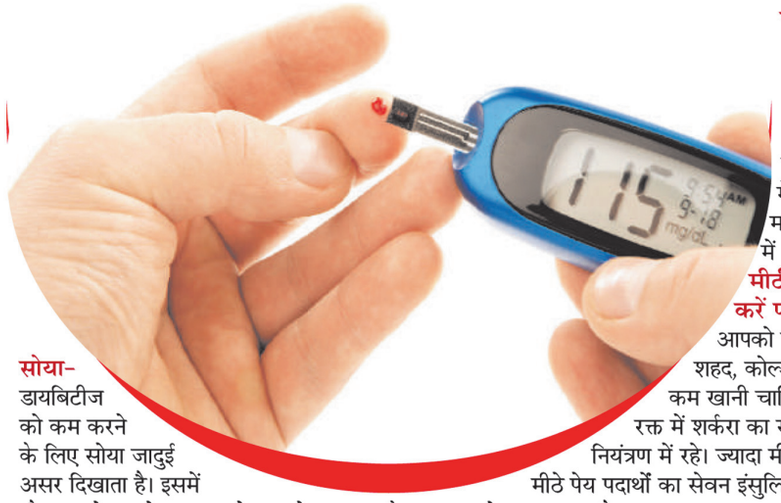

व्यायाम- कसरत करने से खून का दौरा सही रहता है, जिससे खून मेंशक्कर की मात्रा भी काबू में ही रहती है।

मीठी चीजों से करें परहेज- आपको चीनी, गुड़, शहद, कोल्ड ड्रिंक्स आदि कम खानी चाहिए जिससे रक्त में शर्करा का स्तर बिल्ल्कुल नियंत्रण में रहे। ज्यादा मीठी चीजे और मीठे पेय पदार्थों का सेवन इंसुलिन के लेवल को बढ़ा सकता है।

सोया- डायबिटीज को कम करने के लिए सोया जादुई असर दिखाता है। इसमें मौजूद इसोफ्लावोन्स शुगर लेवल को कम कर के शरीर को प्रोषण पहुंचाता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसका सेवन करें।

ग्रीन टी- रोजाना बिना चीनी की ग्रीन टी पीजिए क्योंकि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट होता है जो कि शरीर में फ्रीरैडिकल्स से लड़ाई करता है और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है।

कॉफी- ज्यादा कैफीन लेने से हृदय रोग की समस्या हो सकती है, लेकिन अगर यह हद में रह कर ली जाए तो काफी हद तक यह ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सकती है।

खाने का खास ख्याल- थोड़ी-थोड़ी देर पर खाना नहीं लेते रहने से हाइपोग्लाइसेमिया होने की आशंका काफी बढ़ जाती है, जिसमें शुगर 70 से भी कम हो जाती है। हर ढ़ाई घंटे बाद थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खाना खाते रहें। दिन भर में 3 बार खाने के बजाए थोड़ा-थोड़ा 6-7 बार खाएं।

फाइबर- खून में से शुगर को सोखने में फाइबर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए आपको गेहूं, ब्राउन राइस या वीट ब्रेड आदि खाना चाहिए, जिससे शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल रहेगा, जिससे मधुमेह का रिस्क कम होगा।

ताजे फल और सब्जियां- ताजे फलों में विटामिन ए और सी होता है जो कि खून और हड्डियों के स्वास्थ्य को मेंटेन करता है। इसके अलावा जिंक, पोटैशियम, आयरन का भी अच्छा मेल पाया जाता है। पालक, खोभी, करेला, अरबी, लौकी आदि मधुमेह में स्वास्थ्य वर्धक होती हैं। यह कैलोरी में कम और विटामिन सी, बीटा कैरोटीन और मैगनीशियम में ज्यादा होती हैं, जिससे मधुमेह ठीक होता है।

दालचीनी- दालचीनी, शरीर की सूजन को कम करता है तथा इंसुलिन लेवल को नियंत्रित करता है। इसको आप खाने, चाय या फिर गरम पानी में एक चुटकी दालचीनी पाउडर मिक्स कर पीएं।

टैंशन से दूर रहें- ऑक्सीटोसिन और सेरोटिन दोनों ही नसों की कार्यक्षता पर असर डालते हैं। तनाव होने पर एड्रानलिन का रिसाव होता है तब यह डिस्टर्ब हो जाता है और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है।

उच्च प्रोटीन डाइट- जो लोग नॉन वेज खाते हैं उन्हें अपनी डाइट में लील मीट शामिल करना चाहिए। उच्च प्रोटीन डाइट खाने से शरीर में ताकत बनी रहती है क्योंकि मधुमेह रोगियों को कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट से दूर रहने के लिए कहा गया है।

खूब पानी पीएं- पानी खून में बढ़ी शुगर को इक्ट्ठा करता है, जिस वजह से आपको 2.5 लीटर पानी रोजाना पीना चाहिए। इससे ना ही आपको हृदय रोग होगा और ना ही डायबिटीज।

नमक पर रोक- नमक की सही सीमा आपको डायबिटीज को कंट्रोल करने मे मदद करेगा। ज्यादा नमक खाने से शरीर में हार्मोनल खराबी पैदा हो जाती है। इससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है।

सिरका- खून मे एकाग्र शुगर को सिरका खुद के साथ घोल कर हल्का कर देता है। स्टडी में कहा गया है कि भोजन करने के पहले 2 चम्मच सिरका लेने से ग्लूकूज का फ्लो कम हो जाएगा।

40 पार मां बनना चाहती हैं, तो रखें इन बातों का ध्यान

एक अध्ययन से पता चला है कि 95 फीसदी महिलाएं करियर और परिवार के बीच में परिवार को ही चुनती हैं। करियर के तरफ बढने के दौरान, महिलाओं पर मां बनने का भी दबाव होता है क्योंकि इसमें देरी करने पर उम्र बढ़ने से मां बनने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से वे अपने करियर में सहयोगियों से बेहतर होते हुए भी पिछड़ती जाती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं अपना करियर बीच मे नहीं छोड़तीं और 40 पार कर जाने के बाद भी मां बनने के सपने को साकार करना चाहती हैं। लेकिन महिलाओं की प्रजनन क्षमता 35 की उम्र आते-आते कम होनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वे इस उम्र के बाद प्रेगनेंट नहीं हो सकतीं। आप अगर 40 पार भी मां बनने की इच्छा रखती हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी प्रजनन क्षमता बरकरार रहे। उम्र बढने के साथ एग की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों कम होती जाती है। 25 से 30 वर्ष की उम्र में अपना एग फ्रीज कराकर अपने मां बनने के सपने को 40 साल की उम्र में भी पूरा कर सकती हैं।

- सही प्रकार के प्रोटीन प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं; टोफू, चिकन, अंडे, और कुछ सी-फूड्स में उच्च स्तर पर ओमेगा -3 फैटी एसिड, लोह-तत्व, सेलेनियम इत्यादि पाए जाते हैं। आपके विटामिन में फोलिक एसिड, कैल्शियम और लोह-तत्व मौजूद हों। इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, साबुत अनाज और दालें खाएं। किसी भी तरह के यौन रोग न हों, इसके लिए सेफ सेक्स पर गौर करें।

- वजन कम करें। अध्ययन बताते हैं की मोटापे से ग्रस्त महिलाओं को गर्भधारण करने में ज्यादा कठिनाई आती है और उन्हें गर्भावस्था के दौरान अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स (बी.एम.आई.) थोड़ा अधिक है, तो डाइट ठीक करें और साथ ही एक्सरसाइज भी करें या फिर योगाभ्यास शुरू करें।
- धूम्रपान त्यागें। यह न सिर्फ गर्भावस्था के लिए हानिकारक है अपितु यह गर्भ धारण करने में भी बाधा पैदा कर सकता है।
- एक कहावत है कि हंसी सबसे अच्छी दवा है। अधिकांश डॉक्टर भी मानते हैं कि यह 100 प्रतिशत सही है। तो फिर दिल से क्यों न हंसा जाए। अगर आप जोर से हंसती हैं या मुस्कराती भी हैं तो आपके शरीर में फील गुड हारमोन्स का स्त्रव होता है, जो तनाव पैदा करने वाले कोर्टीसोल नामक हार्मोन को नष्ट करता है। इससे आप ज्यादा सेहतमंद रह पाएंगी। हंसने से चेहरे की माशपेशियों का भी व्यायाम हो जाता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

अन्नामलाई ने छोड़ी भाजपा पार्टी

नईदिल्ली। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को पांच पन्नों का इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा सौंपने के बाद अन्नामलाई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इसके बाद चेन्नई रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक नितिन नबीन और संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ हुई बैठक में अन्नामलाई ने सौहार्दपूर्ण माहौल में पार्टी से अलग होने की इच्छा जताई। उन्होंने साफ कहा कि अब वह अपना रास्ता खुद तय करना चाहते हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी नेतृत्व अन्नामलाई को रोकने की कोशिश कर रहा था और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई अहम भूमिका सौंपी जा सकती थी। उन्हें अगले निर्देश तक दिल्ली न छोड़ने की सलाह भी दी गई थी। बता दें अन्नामलाई के इस्तीफे की अटकलें कुछ महीनों से चल रही थीं, खासकर जब 2025 में उनकी जगह नैनार नागेंद्रन को तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था।

जर्मन राजनेता मारियो ने जयशंकर से की मुलाकात

नईदिल्ली। जर्मनी के थ्यूरिंगिया राज्य के मिनिस्टर-प्रेसिडेंट मारियो वोग्ट ने मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों के बीच व्यापार और तकनीकी साझेदारी को लेकर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने इसकी जानकारी एक्स पर दी। उन्होंने इस मुलाकात को हर्ष का विषय बताया और पोस्ट में लिखा- थ्यूरिंगिया के मिनिस्टर-प्रेसिडेंट मारियो वोग्ट और उनके प्रतिनिधिमंडल से मिलकर खुशी हुई। भारत-जर्मनी और भारत-यूरोपीय संघ संबंधों के विस्तार के प्रति उनका मजबूत सहयोग स्वागतयोग्य है। दोनों की व्यापार और प्रौद्योगिकी साझेदारियों पर सार्थक चर्चा हुई।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को ही मारियो वोग्ट और उनके प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ बैठक की। इस दौरान स्मार्ट शहरी विकास, टिकाऊ बुनियादी ढांचा, डिजिटल प्रशासन, नवाचार, कौशल विकास और प्रतिभा आदान-प्रदान जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में परिवहन, जल प्रबंधन, पर्यावरणीय तकनीकों, शिक्षा और कार्यबल विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ।

संयुक्त राष्ट्र धन की भारी कमी से जूझ रहा है: अमीना मोहम्मद

न्यूयार्क। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर से मदद की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसकी विकास समन्वय प्रणाली धन की भारी कमी से जूझ रही है। एजेंसी ने विभिन्न देशों में अपने काम को मजबूत करने के लिए अपनी नई यूएन80 पहल के तहत तुरंत सुधार करने की अपील की है।

संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना मोहम्मद ने न्यूयॉर्क में एक बैठक में कहा कि इस समय दुनिया भर में विकास को लेकर उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन साथ ही संकट, कर्ज का बोझ और असमानता भी तेजी से बढ़ रही है।

सुश्री अमीना ने आगाह किया कि बजट में हो रही कटौती की वजह से संयुक्त राष्ट्र को कई देशों से अपना दायरा समेटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सदस्य देशों से मिलने वाली मदद में भारी कमी के कारण दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र को अपने काम और कर्मचारियों को लेकर बेहद कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना शुरू

नईदिल्ली।पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी बुधवार को राज्य की नई अन्नपूर्णा योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों को हर महीने 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अन्नपूर्णा योजना भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणापत्र के प्रमुख वादों में शामिल थी। यह योजना पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार की लक्ष्मीर भंडार योजना की जगह लेगी। लक्ष्मीर भंडार योजना के तहत महिलाओं को अधिकतम 1,500 रुपये प्रतिमाह मिलते थे।राज्य सचिवालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, योजना का शुभारंभ 3 जून को किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग ने सभी जिला प्रशासन को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं।आदेश में कहा गया है कि योजना के लाभार्थी ब्लॉक और नगर निकाय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे।

विवाहित बेटियों को अनुकंपा लाभ से बाहर रखना असांविधानिक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केवल शादीशुदा होने के आधार पर किसी बेटी को अनुकंपा के आधार पर सरकारी लाभ या उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) का आवंटन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना असांविधानिक, लैंगिक भेदभाव है। यह समानता तथा भेदभाव-निषेध के सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कुलसुम निशा की याचिका स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट, उपायुक्त और उप-जिलाधिकारी (एसडीएम) के आदेशों को रद्द कर दिया। इन आदेशों में केवल इस आधार पर उनका दावा खारिज किया गया था कि वह शादीशुदा बेटी हैं।कुलसुम निशा ने अपनी मां की मृत्यु के बाद राशन दुकान के आवंटन की मांग की थी। उनकी मां उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में उचित मूल्य की दुकान चलाती थीं। उनका आवेदन एक सरकारी आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था।

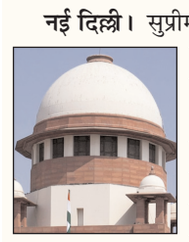

शुभेंदु सरकार के खिलाफ टीएमसी का हल्लाबोल

इजाजत नहीं मिलने पर भी धरने पर बैठीं ममता बनर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) 15 साल के बाद सत्ता से बेदखल हुई है। 15 साल बाद तृणमूल को उखाड़ फेंकने वाली भाजपा आत्मविश्वास से लबरेज है। तृणमूल कांग्रेस इस करारी हार के बाद चुनाव में धांधली के आरोप लगा रही है। दोनों दलों के आक्रामक तेवरों के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध-प्रदर्शन का एलान किया। टीएमसी की तरफ से हुए इस हल्लाबोल के बीच भाजपा ने सोनारपुर में हुई मारपीट और हिंसा के मामले में तृणमूल को घेरा है। भाजपा नेता समिक भट्टाचार्य ने कहा है कि उनके दल पर तृणमूल के ऐसे राजनीतिक हथकंडों का कोई असर नहीं पड़ेगा।

मंगलवार को टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी अपने आवास से निकलने के बाद कोलकाता के रानी रासमणि एवेन्यू पहुंचीं। विरोध-प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि भले ही कोलकाता पुलिस ने उन्हें धरने की इजाजत नहीं दी है, वे लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन जारी रखेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने बंगाल चुनाव जीतने के लिए 294 में से 177 विधानसभा सीटों पर मतगणना में धांधली की है। ममता कोलकाता में वे सांसद कल्याण बनर्जी समेत कई अन्य नेताओं के साथ वाई सर्किल पर शुभेंदु सरकार के खिलाफ धरना दे रही हैं।

कोलकाता में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि आने वाले दिनों में और बड़े विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कोलकाता पुलिस आयुक्त और पुलिस अधिकारियों से कहा कि उनका वेतन जनता के टैक्स के पैसे से दिया जाता है और उन्हें संविधान तथा कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए।

कल्याण बनर्जी ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी

शांतिनिकेतन से पैसा लाकर पुलिस का वेतन नहीं देते हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को याद दिलाया कि समय हमेशा बदलता रहता है, इसलिए सभी को अपनी ड्यूटी निष्पक्ष तरीके से करनी चाहिए। टीएमसी नेता के इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है।

कल्याण बनर्जी ने कहा कि 29 मई को ही प्रशासन को 2 जून के धरना प्रदर्शन की जानकारी दे दी गई थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने आखिरी समय तक कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि देर रात अनुमति मिलने के कारण प्रदर्शन स्थल पर साउंड सिस्टम और स्पीकर नहीं लगाए जा सके। टीएमसी ने इसे प्रशासन की जानबूझकर की गई देरी बताया है।

इससे पहले टीएमसी नेताओं ने पार्टी के नेताओं पर हुए हमलों के विरोध में प्रदर्शन किया। तृणमूल इसलिए भी आक्रामक है भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ सोनारपुर में मारपीट होने के अलावा कई अन्य नेताओं के साथ भी कथित तौर पर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने कहा कि तृणमूल नेताओं के इस विरोध-प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य नेताओं के खिलाफ हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज उठाना है।

नीट-यूजी पेपर लीक मामला

पूरी पीढ़ी से विश्वासघात कर रही है मोदी सरकार : थरूर

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 2 जून को राष्ट्रीय परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने नीट-यूजी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक विवाद पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने बार-बार हो रही असफलताओं को पूरी पीढ़ी के साथ विश्वासघात बताया। मीडिया को संबोधित करते हुए थारूर ने कहा कि यदि आप ऐसी प्रक्रिया चलाते हैं जहां परीक्षाओं की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जहां आप ऐसी स्थिति में हैं जहां दुर्भाग्य से, जिन लोगों ने तैयारी में इतना प्रयास किया है, उन्हें अचानक पता चलता है कि लीक हो गए हैं, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, और पूरी प्रक्रिया दूषित हो गई है, तो कभी-कभी परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं, और उन्हें फिर से शुरू करना पड़ता है।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में भारतीय परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुनिया भर में कई प्रतियोगी परीक्षाएं निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाती हैं, चाहे वह एसएटी हो, कैम्ब्रिज परीक्षा हो, आईएससी हो या कोई और। ऐसा क्यों है कि केवल हमारी सरकार द्वारा संचालित परीक्षाएं ही लगातार गड़बड़ी का शिकार हो रही हैं? सरकार ऐसी स्थिति में क्यों है कि वह राष्ट्रीय परीक्षा जैसी सरल प्रक्रिया की निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा की गारंटी नहीं दे पा रही है?

बार-बार होने वाले संकटों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए थरूर ने कहा कि यह सचमुच सरकार की खामी है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाने चाहिए। अन्यथा, यह पूरी पीढ़ी के साथ विश्वासघात होगा। हम केवल सरकार को ही दोषी ठहरा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार, मंत्रालय, राष्ट्रीय कृषि प्रशासन, वे सभी लोग जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की समग्र जिम्मेदारी है। ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए।

केरल में महंगाई पर विधानसभा में रार, विपक्ष ने किया वॉकआउट

मुख्यमंत्री वीडी सतीशन बोले- टैक्स पर राहत देने पर कर रहे विचार

तिरुवनंतपुरम। केरल विधानसभा में महंगाई पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने सरकार के रुख पर नाराजगी जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं सीएम वीडी सतीशन ने भी विपक्ष के आरोपों से नाराज होकर राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने का एलान कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बावजूद महंगाई कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। इस पर सीएम वीडी सतीशन ने आरोप लगाया कि पिछले 11 महीनों में महंगाई तेजी से बढ़ी है और पिछली एलडीएफ सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं किया।

सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम पिनाराई विजयन ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने बढ़ती महंगाई के गंभीर मुद्दे पर ठीक से चर्चा न करते हुए केवल औपचारिक टिप्पणी कर बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से राज्य में गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद माना है कि हालात आगे और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने इस बढ़ोतरी के पीछे पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को प्रमुख कारण बताया।

विपक्ष नेता ने कहा कि पहले केंद्र सरकार के पास ईंधन मूल्य निर्धारण पर नियंत्रण था, लेकिन बाद में इसे तेल कंपनियों को सौंप दिया गया—जिसकी

शुरुआत कांग्रेस के कार्यकाल में हुई और आगे इसे भाजपा सरकार ने जारी रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि तेल कंपनियां भारी मुनाफा कमा रहीं थी, लेकिन सरकारें प्रभावी नियंत्रण लगाने में विफल रही है।

महंगाई गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है और सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जब एलडीएफ सरकार सत्ता में आई थी, तब टैक्स नहीं बढ़ाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सदन में इस मुद्दे पर उचित चर्चा से बच रही है, इसलिए उनकी पार्टी सदन से वॉकआउट कर रही है।

पी विजयन के आरोपों पर मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से परेशानी होने की बात स्वीकार की और ये भी चेताया कि खाड़ी युद्ध के चलते आगे हालात और बिगड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया कि सरकार महंगाई घटाने के लिए कुछ नहीं कर रही है। सीएम ने कहा कि ठोस कदम उठाने के लिए सरकार को कुछ और समय चाहिए। सीएम ने कहा कि ओमान चांडी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त करों में छूट दी गई थी, जिससे राज्य को लगभग 619 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ था।

उन्होंने एलडीएफ को घेरते हुए कहा कि इसके विपरीत, पिछली एलडीएफ सरकार ने ईंधन करों के माध्यम से करीब 3,100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय इकट्ठा की और करों में कोई कटौती नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कहा था कि एलडीएफ सरकार करों में कटौती करने जैसी गलती नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 महीनों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है लेकिन पिछली एलडीएफ सरकार इस स्थिति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में असफल रही थी।

उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी तथा एलपीजी की कमी को रोकने के लिए भी मजबूत हस्तक्षेप किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार प्रदेश में ईंधन पर लगे अतिरिक्त कर में राहत देकर जनता के बोझ को कुछ कम करने पर विचार कर रहे हैं। सीएम ने ये भी कहा कि सरकार जल्द ही राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करेगी, जिसमें सभी सवालों के जवाब होंगे।

खेल
प्रमुख समाचार

अफगानिस्तान वनडे सीरीज हार्दिक की फिटनेस पर सस्पेंस

नईदिल्ली। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 13 जून से धर्मशाला में शुरू होगी। दूसरा मुकाबला 17 जून को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि तीसरा और अंतिम वनडे 20 जून को चेन्नई में होगा।

भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम में चुना गया है, लेकिन उनकी उपलब्धता अभी फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर है। आईपीएल 2026 के दौरान मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए पीठ में ऐंठन (बैक स्पाज्म) की समस्या से जूझने वाले हार्दिक अब अपनी फिटनेस साबित करने के लिए बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) पहुंचेंगे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हार्दिक 2 जून को सीओई में रिपोर्ट किया और अफगानिस्तान सीरीज से पहले एक सप्ताह से अधिक समय वहीं बिताएंगे। इस दौरान वह फिटनेस ड्रिल, मैच सिमुलेशन और मेडिकल आकलन से गुजरेंगे। सभी टेस्ट सफलतापूर्वक पास करने के बाद ही उन्हें 'रिटर्न टू प्ले' (आरटीपी) की मंजूरी मिलेगी।

हार्दिक पंड्या ने आखिरी बार मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ढ्ढष्टष्ट चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत के लिए वनडे मैच खेला था। इसके बाद चोट और वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण वह इस फॉर्मेट से दूर रहे। अब चयनकर्ताओं ने उन्हें अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम में शामिल तो किया है, लेकिन उनके नाम के साथ फिटनेस शर्त भी जोड़ी गई है।

भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा*, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या*, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स में 380 अंकों की छलांग, निफ्टी 23,523 पर बंद

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए। आईटी, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में खरीदारी से बाजार को समर्थन मिला। हालांकि निवेशकों की नजर भारत-अमेरिका ट्रेड डील के पहले चरण से जुड़ी अहम जानकारियों पर बनी हुई है। निफ्टी 50 100.95 अंक या 0.43 प्रतिशत की तेजी के साथ 23,483.55 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 382.50 अंक या 0.52 प्रतिशत चढ़कर 74,649.84 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज शामिल रहे। आईटी सेक्टर में मजबूत खरीदारी देखने को मिली, जिससे पूरे बाजार की धारणा सकारात्मक रही। ब्रॉडर मार्केट में भी हल्की तेजी दर्ज की गई। निफ्टी मिडकैप 0.18 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 0.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए।

ओमान के साथ एफटीए से आर्थिक सुरक्षा होगी मजबूत

नई दिल्ली। भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता खाड़ी क्षेत्र की अस्थिरता के बीच भारत की ऊर्जा एवं आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। दोनों देशों के बीच यह व्यापार समझौता एक जून से लागू हो गया है। शोध संस्थान सीआरएफ के अध्यक्ष शिशिर प्रियदर्शी ने कहा, पहला, यह अस्थिर क्षेत्र में भारत की ऊर्जा एवं आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करता है। ओमान लंबे समय से खाड़ी में भारत के सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक रहा है। उन्होंने कहा कि भारत तेल, गैस एवं पेट्रोरसायन के आयात पर काफी निर्भर है। ऐसे में ओमान के साथ गहरे आर्थिक एकीकरण से इस महत्वपूर्ण संबंध के लिए अधिक स्थिर और मजबूत ढांचा तैयार होता है। इस मुक्त व्यापार समझौते का महत्व केवल द्विपक्षीय व्यापार आंकड़ों से कहीं अधिक है।

तिमाही रिपोर्ट नहीं देने पर पांच एआईएफ का पंजीकरण रद्द

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को अनिवार्य तिमाही गतिविधि रिपोर्ट जमा करने में बार-बार नाकाम होने पर पांच वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) का पंजीकरण रद्द कर दिया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने अलग-अलग आदेशों में एक्सपोनेंशियल इनोवेशन फंड, फ्लोरिनट्री इंडिया फ्लेक्सी एडवांटेज ट्रस्ट, प्राइम रियल्टी कैपिटल, रुद्राभिषेक इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट और विक्ट्री इन्वेस्टमेंट फंड का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द किया। नियामक ने कहा कि इन वैकल्पिक निवेश कोषों ने मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर, 2025 तिमाहियों के लिए अनिवार्य तिमाही गतिविधि रिपोर्ट दाखिल नहीं की, जबकि नियमों के तहत पंजीकृत एआईएफ के लिए ऐसा करना जरूरी है। मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक, सभी एआईएफ को हर तिमाही खत्म होने के 15 दिन के भीतर सेबी के मध्यस्थ पोर्टल के जरिए रिपोर्ट जमा करनी होती है।

ईडी ने वेदांता ग्रुप के परिसरों पर छापेमारी की

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (श्वष्ठ) ने विदेशी मुद्रा संबंधी कथित उल्लंघन को लेकर वैश्विक खनन समूह वेदांता के खिलाफ जांच के तहत उसके परिसरों पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ऐसा बताया जा रहा है कि अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल से जुड़े इस कारोबारी समूह के खिलाफ छापेमारी सोमवार को शुरू की गई। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली और राजस्थान स्थित परिसरों के अलावा कुछ अन्य स्थानों में भी छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि जांच विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के दीवानी प्रावधानों के तहत की जा रही है। वेदांता के एक प्रवक्ता ने ईडी की कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि कंपनी प्राधिकारियों को पूरा सहयोग दे रही है और मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध करा रही है।

अपशिष्ट पुनर्चक्रण और एथेनॉल नीति में सुधार जरूरी

नंदुला रघुराम

पश्चिम एशियाई संघर्ष के कारण दुनियाभर में सामान की आवाजाही व आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है, जिससे ईंधन और उर्वरकों की कीमतें बढ़ गई हैं। इसी बीच भारत कई दशकों की सबसे भीषण गर्मी तथा कमजोर मानसून जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालांकि, इन समस्याओं की कुछ वजहें वैश्विक हालात हैं, पर कई मुश्किलें हमारी अपनी नीतियों और कमजोरियों का भी परिणाम हैं।

स्थिति और चिंताजनक तब हो जाती है, जब एक तरफ पीने के पानी और खेती के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है, और दूसरी तरफ हम बायोएथेनॉल उत्पादन को तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं। इस्तेमाल की गई फसल के आधार पर एक लीटर एथेनॉल बनाने में लगभग चार से दस हजार लीटर तक पानी खर्च होता है। आज स्थिति यह है कि देश अपनी जरूरत की लगभग 20 प्रतिशत दालें आयात करता है, जबकि दालें देश में बढ़ती प्रोटीन की कमी को दूर करने के साथ यूरिया की मांग घटाने में भी मददगार साबित हो सकती हैं।

सूक्ष्म कणों, यानी पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) के कारण लोगों की सेहत प्रभावित हो रही है। फिर भी, अधिकांश कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों को 'फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम' लगाने से छूट दे दी गई है। यह तकनीक सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करती है, जो खेतों से निकलने वाली अमोनिया के साथ मिलकर हवा में खतरनाक सूक्ष्म कण पैदा करती है। वहीं, खेती के लिए जरूरी पोषक तत्व गोबर और सीवेज में बड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं, पर उनके सही पुनर्चक्रण की कमी के चलते रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता बढ़ गई है। खराब अपशिष्ट प्रबंधन से भी जलाशयों में

यूट्रोफिकेशन जैसी समस्या बढ़ रही है, जिससे विभिन्न जलस्रोत धीरे-धीरे दम तोड़ रहे हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में लगभग 90 अरब क्यूबिक मीटर तक कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन की क्षमता मौजूद है, जिससे आयातित प्राकृतिक गैस की आवश्यकता लगभग पूरी तरह खत्म की जा सकती है और घरेलू व औद्योगिक जरूरतों की बड़ी मांग देश के भीतर ही पूरी हो सकती है। इसी दिशा में राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा मिशन, गोबरधन और सतत जैसी योजनाओं के तहत सरकार बायोगैस उत्पादन बढ़ाने तथा गैस मिश्रण को अनिवार्य बनाने के लिए कई प्रोत्साहन दे रही है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद देश की कुल उत्पादन क्षमता लगभग 3,700 टन प्रतिदिन तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत ने 2070 तक 'नेट जीरो', यानी शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य तय किया गया है, उसे हासिल करने के लिए मौजूदा नीतियों और योजनाओं की गति अभी पर्याप्त नहीं है। इन पहलों का दायरा तथा प्रभाव, दोनों को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। उनका सुझाव है कि रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल तभी किया जाए, जब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सभी जैविक विकल्प-जैसे गोबर खाद, कंपोस्ट, बायोचार व अन्य जैविक स्रोत पूरी तरह उपयोग में लाए जा चुके हों। अखिल भारतीय समन्वित फसल परीक्षणों में भी यह साबित हो चुका है कि उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा का करीब आधा हिस्सा खाद, कंपोस्ट या बायोचार से बदला जा सकता है और इससे फसल उत्पादन पर कोई नकारात्मक असर भी नहीं पड़ता। पर, समस्या यह है कि सरकारी सिफारिशों और कृषि सलाहों में इन वैकल्पिक उपायों को पर्याप्त जगह नहीं मिल पाई है। नतीजतन, किसान रासायनिक उर्वरकों को ही आधार खुराक मानकर उनका अत्यधिक उपयोग करते हैं।

जरूरत इस बात की भी है कि अनाज और खाद्य फसलों से बनने वाले एथेनॉल को हतोत्साहित किया जाए और इसके उत्पादन के लिए केवल शीरा (मोलासेस) तथा अन्य बेकार बायोमास के इस्तेमाल की ही अनुमति दी जाए। नीति आयोग के अनुसार, दिल्ली, बंगलूरू और चेन्नई समेत भारत के 21 बड़े शहरों में वर्ष 2030 तक भूजल पूरी तरह समाप्त होने का खतरा है।

हर गांव तक पहुंचेगी विकास की रोशनी : चौधरी

■ वित्त मंत्री ने 32.15 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

रायपुर। प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी ने अपने जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर पुसौर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत मिडमिडा, त्रिभौना, तुरंगा, कोतासुरा एवं कोड़ातराई का दौरा कर करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास, भूमिपूजन एवं लोकार्पण करते हुए क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने का संकल्प दोहराया। इस दौरान कुल 32 करोड़ 15 लाख रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।

ग्रामीणों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि प्रदेश और रायगढ़ की जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है, उसे विकास कार्यों के माध्यम से सार्थक करना उनका दायित्व है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिले का समग्र एवं संतुलित विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और प्रत्येक गांव तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए युग की ओर अग्रसर है। प्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना है। गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

श्री चौधरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिससे गांव और शहर के बीच विकास का अंतर कम हो सके। उन्होंने कहा कि आज जिन कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है, वे केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि क्षेत्र के हजारों लोगों के बेहतर भविष्य की मजबूत आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कें किसी भी क्षेत्र की प्रगति का आधार होती हैं। इससे किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी, विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज जाने में आसानी होगी तथा स्थानीय व्यापार और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। वहीं मिनी स्टेडियम जैसे निर्माण कार्य ग्रामीण युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे।

26.80 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों का शिलान्यास

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने 26 करोड़ 80 लाख रुपये से अधिक लागत के चार महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें त्रिभौना-कोड़पाली पहुंच मार्ग पर 2.80 करोड़ रुपये की लागत से 1.50 किलोमीटर सीसी सड़क निर्माण कार्य। मिडमिडा हाईस्कूल पहुंच मार्ग पर 1.24 करोड़ रुपये की लागत से 0.70 किलोमीटर सीसी सड़क निर्माण कार्य। मचिदा-कलमी मार्ग पर 3.04 करोड़ रुपये की लागत से 3.50 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य। कोड़ातराई-पुसौर-सूरजगढ़ मार्ग पर 19.71 करोड़ रुपये की लागत से 6.70 किलोमीटर सीसी सड़क निर्माण कार्य।इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच और बेहतर बनेगी।

5.35 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण: वित्त मंत्री श्री चौधरी ने 5 करोड़ 34 लाख 82 हजार रुपये की लागत से पूर्ण हुए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया।

इनमें लोक निर्माण विभाग द्वारा 3 करोड़ 92 लाख 39 हजार रुपये की लागत से निर्मित गोतमा-कोतासुरा मार्ग (3.50 किलोमीटर) प्रमुख रूप से शामिल है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान

■ मध्यम उपभोक्ता आधार वाले राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक वेंडर रजिस्ट्रेशन में देश में दूसरा स्थान

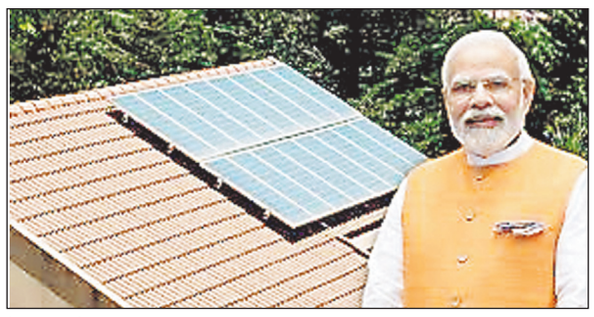

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर = मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आयोजित "Month of Solar" अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाना राज्य के लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य में स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में किए जा रहे सतत प्रयासों का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मध्यम उपभोक्ता आधार वाले राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक वेंडर रजिस्ट्रेशन के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए राज्य का चयन पीएम सूर्यघर एक्सीलेंस अवार्ड हेतु किया गया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि ऊर्जा क्षेत्र में राज्य की सक्रियता, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनसहभागिता का सकारात्मक परिणाम है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए ऊर्जा विभाग, क्रेडा, विद्युत वितरण कंपनियों, सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सहयोगी संस्थाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि टीमवर्क, प्रतिबद्धता और बेहतर समन्वय के कारण छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार ऊर्जा आत्मनिर्भर, पर्यावरण अनुकूल और हरित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले ऐसे प्रयास प्रदेश के नागरिकों को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ स्वच्छ एवं सतत विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

दीपक बैज का बयान आदिवासी-विरोधी राजनीति को छिपाने का प्रयास : कश्यप

रायपुर। वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को आदिवासी हितों पर सवाल उठाने से पहले अपना राजनीतिक इतिहास देखना चाहिए। जिन कानूनों और अधिकारों की आज कांग्रेस बात कर रही है, उनके प्रभावी क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा स्वयं कांग्रेस की नीयत और नीतियां रही हैं।कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक समझकर राजनीति की, लेकिन उन्हें उनके अधिकारों, संसाधनों और विकास से जोड़ने का ईमानदार प्रयास कभी नहीं किया। आज जब छत्तीसगढ़ में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने, वनाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आदिवासी समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, तब कांग्रेस इसे भी राजनीतिक चश्मे से देख रही है।उन्होंने कहा कि दीपक बैज और कांग्रेस को यह बताना चाहिए।

कि वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद पीईएसए और वनाधिकार कानून का लाभ अंतिम व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच सका। आदिवासी क्षेत्रों में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और आजीविका के अवसरों का अभाव किसकी देन था, यह देश अच्छी तरह जानता है।

वन मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का वास्तविक दर्द आदिवासी अधिकार नहीं, बल्कि आदिवासी क्षेत्रों में उसका लगातार सिकुड़ता जनाधार है। आज वनवासी समाज जागरूक हो रहा है, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रहा है और विकास प्रक्रिया में भागीदार बन रहा है, यही बात कांग्रेस को परेशान कर रही है।

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासी गौरव, आदिवासी अधिकार और आदिवासी विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार भी इसी भावना के साथ कार्य कर रही है। कांग्रेस के आरोप तथ्यहीन, राजनीतिक रूप से प्रेरित और आदिवासी समाज को भ्रमित करने का असफल प्रयास हैं।

'सीएम हेल्पलाइन (1076) के नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न'

रायपुर। सुशासन एवं अभिसरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आज मंत्रालय (महानदी भवन) नवा रायपुर में सीएम हेल्पलाइन (1076) के विभागीय नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में शासन के सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन आम नागरिकों तक सुशासन पहुँचाने का सबसे सशक्त और सुलभ माध्यम है। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आम जनता की शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों को आधुनिक शिकायत प्रबंधन प्रणाली के व्यावहारिक उपयोग की जानकारी दी गई। शिकायतों का समय पर निराकरण न होने की स्थिति में उन्हें प्रक्रिया, एल-1 से एल-4 स्तर तक स्वचालित रूप से ट्रांसफर करने की तकनीकी प्रक्रिया समझाई गई। नागरिकों से उनकी संतुष्टि का फीडबैक लेने की पारदर्शी प्रक्रिया के बारे में बताया गया।

'रायपुर में जेम्स पार्क और बिलासपुर में बनेगा आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर'

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम की सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य की महत्वाकांक्षी औद्योगिक, वाणिज्यिक और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को गति देने के लिए विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

रायपुर के कृषि उपज मंडी परिसर (मंडी रोड) में अत्याधुनिक रत्न एवं आभूषण पार्क (रायपुर जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क) बनाने की योजना है। बिलासपुर शहर में बढ़ते भारी वाहनों के दबाव और ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए एक विशाल सर्व-सुविधायुक्त ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा। यहाँ बड़े गोडाउन, लॉजिस्टिक्स हब, व्यापक पार्किंग स्पेस, वाहन रिपेयरिंग सेंटर और चालकों के लिए रेस्ट एरिया जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

नवा रायपुर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजनों के लिए एक वर्ल्ड-क्लास कन्वेंशन सेंटर विकसित किया जाएगा। यह अत्याधुनिक बिजनेस हब कॉर्पोरेट इवेंट्स, ग्लोबल बिजनेस मीट और प्रदर्शनियों के लिए उपयुक्त होगा, जिससे छत्तीसगढ़ में बिजनेस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इन सभी बड़ी परियोजनाओं को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित करने की रूपरेखा तैयार की गई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, नीति आयोग के सदस्य सचिव आशीष भट्ट, वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा सहित छत्तीसगड राज्य औद्योगिक विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

आदिवासी समाज को प्रताड़ित कर रही सरकारः दीपक बैज

रायपुर। सरकार पर से आदिवासी समाज का भरोसा उठ गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार आदिवासी समाज को प्रताड़ित कर रही है। राज्य के आदिवासी, सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे है। अपने जल, जंगल, जमीन और संस्कृति को बचाने के लिए बालोद में आदिवासी समाज के 10 हजार से अधिक लोग कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर रात 11 बजे तक धरने पर बैठे रहे। पूरे प्रदेश में

आदिवासी समाज सरकार की कार्यप्रणाली से आक्रोशित है। इसके पहले कवर्धा में भी आदिवासी समाज अपनी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर का घेराव कर चुके है। भाजपा के राज में सुनियोजित तरीके से आदिवासियों पर उनकी संस्कृति पर हमले हो रहे। भाजपा सरकार जल, जंगल, जमीन पर से आदिवासियों के मौलिक और नैसर्गिक अधिकार से वंचित करने का षड़यंत्र कर रही है। पेसा कानून को कमजोर किया जा रहा है, केंद्र ने वन अधिकार अधिनियम 2006 में संशोधन कर दिया है। आदिवासियों को बेदखल करने की कोशिशों का कांग्रेस विरोध करती है। हसदेव के जंगल से लेकर तमनार के जंगल और बस्तर के बैलाडीला हाहालदी तक सरकार के मित्रों की नजर लग गयी है।

विधायक टोप्पो को तत्काल गिरफ्तार किया जायेः शुक्ला

रायपुर। कांग्रेस तहसीलदारो तथा राजस्व अधिकारी संघ के हड़ताल को जायज बताया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा विधाक रामकुमार टोप्पो की तत्काल गिरफ्तारी की जानी चाहिये। उन्होंने सत्ता बल के अहंकार में अपनी मर्यादा का उल्लघंन किया है तथा नायब तहसीलदार के साथ मारपीट किया है। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी दोषी विधायक को गिरफ्तार करवाने के बजाये

उनकी पैरोकार बनी हुई है। इस घटना को एक सप्ताह बीत गया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं किया गया। उपर से भाजपा आरोपी विधायक के साथ खड़ी हो गयी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि विधायक को अधिकारी कार्यप्रणाली पर आपत्ति थी तो वे उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से कर सकते थे, मुख्यमंत्री, मंत्री से कर सकते थे। उन्हें मारपीट करने का अधिकार किसने दिया। भाजपा प्रदेश में तालिबानी सरकार चलाना चाह रही है।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस मामले में भाजपा संगठन का बयान बेहद आपत्तिजनक है कि हम अपने विधायक के साथ है। यह बयान लोकतंत्र को मुंह चिढ़ाने वाला है।

स्वास्थ्य विभाग में ठेका से सलाहकार की नियुक्ति : ठाकुर

रायपुर। स्वास्थ्य विभाग में ठेका से सलाहकर की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुये प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल से पूछा स्वास्थ्य सेवा संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन में आखिर अलग से ठेका में सलाहकर रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसको खुश करने सरकारी खजाने से सवा करोड़ रु. महीना

सलाहकारों के वेतन में खर्च किया जा रहा है? जबकि स्वास्थ्य विभाग में योजनाओं की निगरानी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईटी सपोर्ट, सप्लाई चैन मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन, डेटा एनालिसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिये अलग-अलग शाखा है। विभाग में ही पूर्व से तकनीकी एवं अन्य विषयों के जानकार कार्यरत है। ऐसे में आखिर दो से चार लाख रु. महीना वेतन के निजी सलाहकार क्यों रखा गया है? सलाहकार का वेतन स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से ज्यादा है। ये तो सीधा-सीधा संघ समर्थकों को पोषित करने की योजना है। स्वास्थ्य मंत्री तत्काल इन ठेका सलाहकारों की नियुक्ति पर रोक लगाये। भाजपा सरकार ने प्रदेश को संघी समर्थकों के लिए चारागाह बना दिया है। सरकारी खजाने को संघियों पर लुटाया जा रहा है।

सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सुरक्षा कवच बनी एचपीवी वैक्सीन

रायपुर। किशोरी बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य में एचपीवी (ह्यूमन पेपिलोमावायरस) टीकाकरण अभियान को व्यापक रूप से संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार के निर्देशानुसार 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को नि:शुल्क एचपीवी वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित इस अभियान का उद्देश्य बालिकाओं को भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे से बचाते हुए उनके स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन की नींव को मजबूत करना है। बलरामपुर जिले में कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में अभियान प्रभावी रूप से संचालित हो रहा है। जिले में अब तक 2084 किशोरी बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामरी में 150 के लक्ष्य के विरुद्ध 142 बालिकाओं का टीकाकरण किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के चिन्हांकित स्वास्थ्य संस्थानों में टीकाकरण का कार्य निरंतर जारी है। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने अभिभावकों एवं किशोरियों से इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहल का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि एचपीवी वैक्सीन गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर की रोकथाम में अत्यंत प्रभावी और पूरी तरह सुरक्षित है।

दो संस्थानों से भारी मात्रा में अवैध खाद जब्त

रायपुर। किसानों को खेती-किसानी के सीजन में नकली और अवैध खाद-बीज से बचाने के लिए रायपुर जिला प्रशासन और कृषि विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। जिले के आरंग विकासखंड में अवैध रूप से उर्वरक का भंडारण और वितरण करने वाले दो संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां भारी मात्रा में अवैध खाद जब्त की गई है। कृषि विभाग के उप संचालक श्री सतीश अवस्थी ने बताया कि आरंग विकासखंड के ग्राम समोदा स्थित मेसर्स महानदी बीज भंडार द्वारा अपने उर्वरक प्राधिकार पत्र में बिना जरूरी स्त्रोत प्रमाण पत्र दर्ज कराए ही खाद का भंडारण और बिक्री की जा रही थी। मामले की शिकायत मिलते ही क्षेत्रीय उर्वरक निरीक्षक ने बीते 26 मई को मौके पर दबिश देकर 35.05 मीट्रिक टन उर्वरक जब्त कर लिया। इस मामले में उर्वरक आदेश 1985 के नियमों के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह को रिपोर्ट सौंप दी गई है। इसी तरह आरंग के ही ग्राम कलई में अवैध रूप से खाद का स्टॉक जमा कर किसानों को बेचने का एक और बड़ा मामला सामने आया। यहां मेसर्स पुलकित बायो फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अवैध रूप से खाद बेचने की शिकायत ग्रामीणों से मिली थी। शिकायत पर त्वरित एक्शन लेते हुए उर्वरक निरीक्षक दल, क्षेत्रीय पटवारी और आरंग थाने के सहायक उप निरीक्षक की टीम मौके पर पहुंची।

लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय नारायणपुर को मिला 'पर्यावरण चैंपियन अवार्ड 2026'

■ 100 से अधिक नामांकनों में देश की चुनिंदा 9 संस्थाओं में बनाया स्थान, छत्तीसगढ़ को मिला राष्ट्रीय गौरव

रायपुर। पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन, जैव विविधता संरक्षण, जैविक कृषि, वृक्षारोपण, नशामुक्ति जागरूकता एवं जनसहभागिता आधारित पर्यावरणीय अभियानों में उत्कृष्ट एवं नवाचारपूर्ण कार्यों के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के अधीनस्थ लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, नारायणपुर को कल देहरादून में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित पर्यावरण चैंपियन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित नमामि गंगे परियोजना तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में प्रदान किया गया। देशभर से प्राप्त 100 से अधिक नामांकनों में से कठोर मूल्यांकन एवं बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया के पश्चात केवल 9 संस्थाओं को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया, जिनमें एक विश्वविद्यालय, पांच विद्यालय एवं तीन महाविद्यालय शामिल थे।

सम्मानित संस्थाओं में बिहार, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि शामिल थे। चयनित संस्थाओं में उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध सामुदायिक रेडियो रेडियो केदार भी सम्मिलित रहा। ऐसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धी मंच पर नारायणपुर महाविद्यालय का चयन संस्था के उत्कृष्ट पर्यावरणीय कार्यों की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। समारोह के दौरान सभी चयनित प्रतिभागियों एवं संस्थाओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन, वृक्षारोपण एवं जनजागरूकता के क्षेत्र में किए गए कार्यों की वीडियो प्रस्तुति प्रदर्शित की गई।

लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय, नारायणपुर द्वारा प्रस्तुत गतिविधियों एवं उपलब्धियों को उपस्थित विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों एवं प्रतिभागियों द्वारा विशेष सराहना प्राप्त हुई। लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय को यह सम्मान ट्रॉफी एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर दिया गया।

रायपुर में विकसित होगा विश्वस्तरीय हॉस्पिटैलिटी एवं वेलनेस सेंटर

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा राजधानी रायपुर स्थित क्रींस क्लब ऑफ इंडिया के विकास, संचालन एवं रख-रखाव के लिए लाइसेंस आधार पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत एजेंसी नियुक्त करने की महत्वपूर्ण परियोजना प्रस्तावित की गई है। यह पहल रायपुर को एक आधुनिक एवं प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी तथा वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी।परियोजना के तहत क्लब परिसर में स्क्वैश कोर्ट, टेनिस कोर्ट, जिम, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन हॉल, बिलियर्ड रूम तथा टेबल टेनिस हॉल जैसी आधुनिक खेल एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं विकसित एवं संचालित की जाएंगी। साथ ही वर्तमान अधोसंरचना का व्यापक आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण भी किया जाएगा।वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि यह परियोजना रायपुर को एक नए प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे राज्य में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा गुणवत्तापूर्ण शहरी अधोसंरचना विकास को नई गति प्राप्त होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रींस क्लब ऑफ इंडिया की विशेष आवास योजना के अंतर्गत सांसद एवं विधायक वर्ग के 108 सदस्यों की विशेष सदस्यता पूर्ववत जारी रहेगी। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान वर्तमान सदस्यों के हितों एवं सुविधाओं का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि परियोजना को लाइसेंस, डेवलप, ऑपरेट एवं ट्रांसफर मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.